नई दिल्ली
गुरुवार
17 सितंबर 2026
वर्ष: 13, अंक: 14
पृष्ठ: 08, मूल्य 2 रु0
E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
सद्भावना टुडे
आवाज़ अधिकार की

मुख्यमंत्री सम्राट और केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान...पेज-05
DELHIN/2014/58158
युवा शक्ति विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की...पेज-08

प्रधानमंत्री मोदी आज 'सेमीकॉन इंडिया 2026' का करेंगे उद्घाटन

52 देशों के प्रतिनिधियों समेत 600 से अधिक कंपनियां लेंगी हिस्सा

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में सुबह करीब 10 बजे तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 'सेमीकॉन इंडिया 2026' का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। 17 से 19 सितंबर तक आयोजित होने वाले सम्मेलन की थीम 'सिलिकॉन टू सिस्टम्सः बिल्डिंग द इकोसिस्टम' है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, सम्मेलन में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला से जुड़े वैश्विक और भारतीय उद्योगों के साथ नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थान और विद्यार्थी एक साझा मंच पर जुटेंगे। आयोजन का उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल के विकास को गति देना है।

सम्मेलन में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के साथ-साथ डिस्प्ले उद्योग में तकनीकी प्रगति पर समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे। रणनीतिक साझेदारी और संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए छह देशों की गोलमेज बैठकें होंगी। इसके अलावा महिला नेतृत्व पर केंद्रित विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा। 'सेमीकॉन इंडिया 2026' में सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के सभी प्रमुख चरणों को एकीकृत रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर सामग्री और उपकरण से लेकर चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और एकीकृत प्रणालियों तक की पूरी प्रक्रिया शामिल होगी। इस पूरी यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए विशेष 'सैंड टू सिलिकॉन टू सिस्टम्स' वैल्यू चेन अनुभव केंद्र तैयार किया गया है। आयोजकों के अनुसार, सम्मेलन में 52 देशों के प्रतिनिधियों

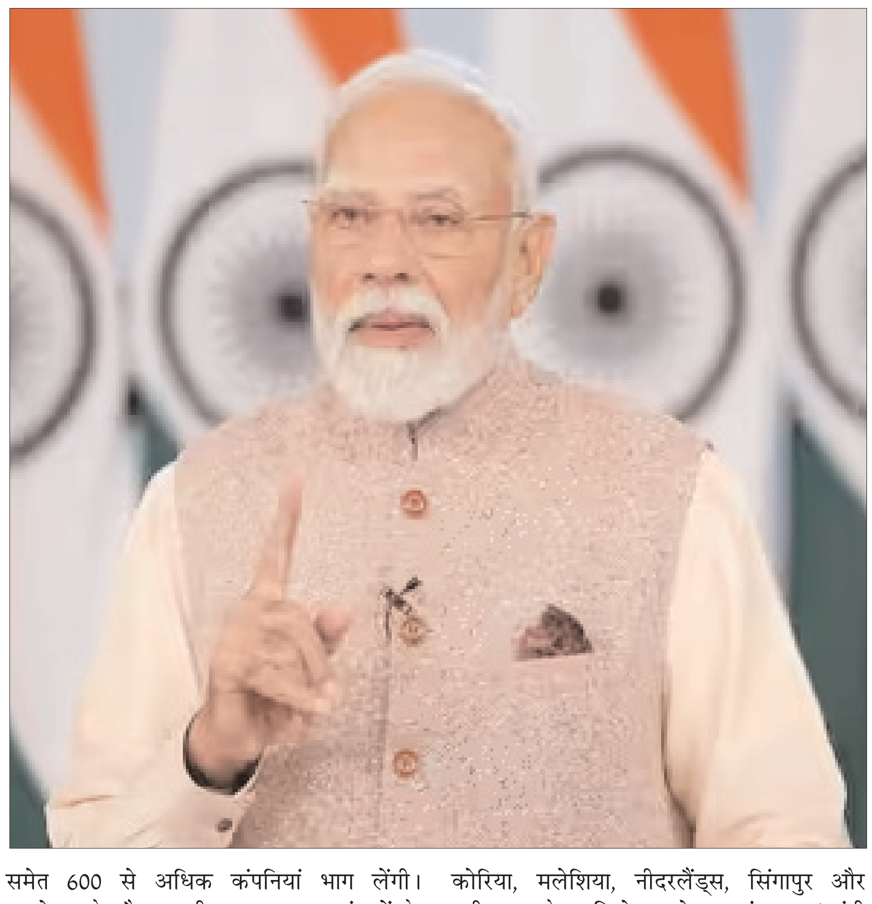

समेत 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। आयोजन के दौरान करीब 50 हजार आगंतुकों के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा 400 से अधिक शीर्ष कार्यकारी और 150 से अधिक वक्ता विभिन्न तकनीकी एवं रणनीतिक सत्रों में अपने विचार साझा करेंगे। प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड्स, सिंगापुर और स्वीडन के विशेष देश मंडप (कंट्री पैवेलियन)बनाए गए हैं। इसके अलावा 12 राज्यों के बूथ, स्टार्टअप पैवेलियन, नवाचार शोकेस, छात्र हैकथॉन और कार्यबल विकास पैवेलियन भी सम्मेलन का हिस्सा होंगे।

एक नजर

सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ रूस के दौरे पर, पेशेवर सैन्य सहयोग पर करेंगे वार्ता

नई दिल्ली। सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ बुधवार को रूस के आधिकारिक दौरे पर रवाना हुए हैं। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रक्षा साझेदारी और सैन्य सहयोग को ज्यादा मजबूत करना है। इस दौरान वे रशियन लैंड फोर्सेज के कमांडर-इन-चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई निकोलायेविच मोर्डविचव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और ट्रेनिंग सहित आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 18 सितंबर तक अपने इस दौरे में मास्को में 'टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर' पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और उन्हें सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जायेगा। सेना प्रमुख मॉस्को में नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों से बातचीत करेंगे, जिसमें रक्षा उद्योग और खरीद से जुड़े डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वासिली सर्गेयेविच ओस्माकोव भी शामिल हैं। इन मुलाकातों से आज के सैन्य विकास और डिफेंस सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर अपनी राय साझा करने का मौका मिलेगा। इस दौरे में जनरल धीरज सेठ सेंट पीटर्सबर्ग भी जाएंगे, जहां वे मिखाइलोव्स्काया मिलिट्री आर्टिलरी एकेडमी जाकर वहां की लीडरशिप और फैकल्टी से बातचीत करेंगे। उनका यह दौरा दिखाता है कि दोनों देश लगातार सैन्य कूटनीति और आर्मी-टू-आर्मी एंगेजमेंट को कितना महत्व देते हैं। इस बातचीत से सैन्य सहयोग मजबूत होने और भारत-रूस के बीच लंबे समय तक चलने वाले रक्षा रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद है।

ईपीएफओ में वेतन सीमा बढ़ाकर 25 हजार की गई, 51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है। सरकार के इस फैसले से 51 लाख से अधिक कर्मचारियों के ईपीएफओ के दायरे में आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वेतन सीमा बढ़ने से 15 हजार से 25 हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि वेतन सीमा को बढ़ाने का आधार यह है कि पिछली बार 15 हजार रुपये की सीमा सितंबर 2014 में निर्धारित की गई थी। इसके बाद औसत वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और जीवन-यापन की लागत भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आज नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारी की औसत मासिक आय करीब 23 हजार रुपये है, जो 2014 से पहले की अवधि की तुलना में लगभग ढाई गुना बढ़ चुकी है। कई राज्यों ने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन भी 15 हजार रुपये से अधिक कर दिया है। सरकार के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में 15 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करने वाला कर्मचारी स्वतः अनिवार्य ईपीएफ व्यवस्था के दायरे में नहीं आता। सीमा बढ़ाकर 25 हजार रुपये किए जाने से ऐसे कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा लाभों का दायरा बढ़ेगा।

झीरम घाटी फैसला: सभी 10 दोषियों को मृत्युदंड, सरकार ने बताया न्याय की जीत, कांग्रेस ने उठाए जांच पर सवाल

रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ की राजनीति को झकझोर देने वाले झीरम घाटी नक्सली हमले के करीब 13 वर्ष बाद जगदलपुर की विशेष एनआईए अदालत ने बुधवार को दो महिलाओं सहित सभी 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। विशेष एनआईए अदालत ने प्रमिला मोडियम, चैतू लेकाम उर्फ मुन्ना, सुमित्रा उर्फ सुमित्रा पुनेम मोडियम, मुक्का मांडवी, कोसा कवासी उर्फ कोसाराम, आयता मरकाम, मदकामी देवा, जोगा मदकामी, बनजामी सन्ना उर्फ चमरू उर्फ डेंगा और महादेव नाग को मृत्युदंड सुनाया है। अदालत ने गत पांच सितंबर को सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष ने मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने सजा कम करने का आग्रह किया था। मृत्युदंड की सजा के क्रियान्वयन के लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होगी। तब तक दोषी केंद्रीय जेल जगदलपुर में रहेंगे। दोषियों के पास फैसले के खिलाफ 30 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने का कानूनी विकल्प है।

फैसले के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारतीय जनता पार्टी ने इसे न्याय की जीत बताते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच की सराहना की, जबकि कांग्रेस ने अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए जांच की दिशा पर सवाल उठाए और कहा कि हमले के 'बड़े षड्यंत्रकारियों' तक जांच अब भी नहीं पहुंची है। झीरम घाटी हमला 25 मई 2013 को हुआ था। सुकमा में आयोजित परिवर्तन रैली के बाद जगदलपुर की ओर लौट रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के काफिले पर माओवादियों ने घात

लगाकर हमला किया। करीब डेढ़ घंटे चले हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके पुत्र दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा और उदय मुदलियार सहित कई लोग मारे गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हुए थे। बाद में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। हमले में कुल 29 लोगों की मौत हुई थी। श्री साय ने फैसले पर कहा, 'झीरम घाटी मामले में 10 माओवादियों को मृत्युदंड की सजा न्याय की जीत है। एनआईए ने जांच को अंजाम तक पहुंचाया, जिसके लिए उसकी सराहना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में प्रदेश को सशस्त्र माओवाद के चंगुल से मुक्त कराया गया है। आतंक को बौद्धिक और वैचारिक समर्थन देने वालों के लिए यह स्पष्ट संदेश है।' उन्होंने झीरम घाटी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए इसे 'आधा-अधूरा न्याय' करार दिया। उन्होंने कहा कि अदालत ने उसके सामने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर फैसला दिया है, लेकिन कांग्रेस एनआईए की जांच को लेकर अपनी पूर्व की राय पर कायम है।

कांग्रेस ने यूपीआई को पहले की तरह पूरी तरह से नि:शुल्क रखने की मांग की

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट भुगतानों पर शुल्क लगाने का रास्ता खोलने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार की निंदा की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिकी कंपनियों के दबाव में आकर देश के आम नागरिकों, युवाओं और व्यापारियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। पार्टी ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने और यूपीआई को पहले की तरह पूरी तरह से नि:शुल्क रखने की मांग की है।

कांग्रेस सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार के नए फैसले के तहत 2,000 रुपये से अधिक के हर मर्चेंट यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) वसूला जाएगा। सरकार की यह दलील पूरी तरह बेमानी है कि यह शुल्क ग्राहक नहीं बल्कि मर्चेंट

चुकाएगा, क्योंकि अंततः व्यापारी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ाकर यह बोझ आम जनता पर ही डालेंगे। श्रीनेत ने दावा किया कि देश में 2,000 रुपये से अधिक मूल्य के 604.8 करोड़ पी2एम (व्यक्ति-से-व्यापारी) यूपीआई लेन-देन होते हैं, जिनका कुल मूल्य 66.22 लाख करोड़ रुपये है। भारत के डिजिटल भुगतान बाजार में फोनपे की 48.9 प्रतिशत और गूगल पे की 37.7 प्रतिशत हिस्सेदारी है। फोनपे में अमेरिका की वॉलमार्ट की 72 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि गूगल पे शत-प्रतिशत अमेरिकी कंपनी गूगल एलएलसी के स्वामित्व वाली है।

शिवसेना में विभाजन मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उठाया अहम सवाल

नई दिल्ली,एजेंसी। शिवसेना और 'धनुष-बाण' चुनाव चिन्ह को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी का स्वामित्व तय करने के लिए विधायी बहुमत को सुरक्षित पैमाना माना जा सकता है, खासकर तब जब उसी बहुमत को बनाने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही चल रही हो। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज एकनाथ शिंदे गुट से ये पूछा। कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल से पूछा कि भले विधायी बहुमत अहम पैमाना है लेकिन क्या यह हमेशा निर्णायक या सुरक्षित पैमाना हो सकता है, खासकर तब जब उन्हीं विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही लंबित हो। इसके पहले इस मामले पर सुनवाई के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कहा गया था कि निर्वाचन आयोग की ओर से एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम और 'धनुष-बाण' का चिह्न आवंटित करने का फैसला गैरकानूनी था।

बड़े राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए कर नीति पर चर्चा होनी चाहिएः सीतारमण

आईटीआरएएफ से कर अनुसंधान को नीति-निर्माण से जोड़ने का किया आह्वान

नई दिल्ली/बेंगलुरु। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि कर नीति (टैक्स पॉलिसी) पर चर्चा छोटे सेक्टर की बातों से ऊपर उठकर बड़े राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित 'इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन' (आईटीआरएएफ) द्वारा 'न्यू एज टैक्सेशन' विषयक 8वें अंतरराष्ट्रीय कर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावों में अलग-अलग रेट कट यानी छूट के बजाय लंबे समय के विकास के लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। मंत्री ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कहा कि वे स्वतंत्र टैक्स पॉलिसी रिसर्च को सार्वजनिक चर्चा का नियमित हिस्सा बनाएं ताकि इसकी जांच की जा सके, इस पर सवाल उठाए जा सकें और इसमें सुधार किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर नीति पर स्वतंत्र शोध को सार्वजनिक विमर्श

का हिस्सा बनना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि कर पेशेवरों को क्षेत्रीय हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। सीतारमण ने कहा भारत में कराधान के क्षेत्र में उच्च स्तर के पेशेवर और विशेषज्ञ हैं लेकिन उनकी विशेषज्ञता को एक साथ लाकर नीतिगत विकल्पों में योगदान देने के लिए मजबूत संस्थागत मंच की जरूरत है।

सीतारमण ने आईटीआरएएफ से स्वतंत्र कर नीति अनुसंधान को अधिक प्रमुखता से सामने लाने और उसे नीति-निर्माण तथा सार्वजनिक विमर्श से सीधे जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सरकार को दिए जाने वाले टैक्स से जुड़े प्रस्तावों में दरों में कटौती, छूट या रियायतें मांगने के बजाय देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने अपने मंत्रालय की बजट-पूर्व चर्चाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि इन चर्चाओं से ऐसे बड़े सवाल उठने चाहिए कि 'विकसित भारत 2047' की ओर बढ़ते हुए अगले दो दशकों में भारत में किस तरह की टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने बेहतर टैक्स रिसर्च पर जोर दिया, जो सभी पहलुओं पर विचार करे। साथ ही इसके असर को मापे, ट्रेड-ऑफ (फायदे-नुकसान के बीच संतुलन) को समझे, सरकारी खजाने को होने वाले हर राजस्व नुकसान के लिए व्यावहारिक विकल्प सुझाए और सरकार को ऐसे विकल्प तैयार करने में मदद करे, जिनसे एक अच्छी टैक्स पॉलिसी बन सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के फिनिशर मेडल का किया अनावरण

नई दिल्ली। वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेबल रेस-वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 21वें संस्करण के प्रतिष्ठित फिनिशर मेडल का बुधवार को अनावरण किया गया। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मेडल का अनावरण किया। यह मेडल हर धावक के लिए उपलब्धि और फिनिश लाइन तक पहुंचने की उसकी मेहनत का प्रतीक है।

वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन रविवार, 18 अक्टूबर 2026 को प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होगा। भारत और दुनिया भर से हजारों धावक राजधानी की सड़कों पर एक लक्ष्य के साथ उतरेंगे और होगा फिनिश लाइन पार करना और अपना मेडल हासिल करना। पिछले दो दशकों में

यह आयोजन दिल्ली की खेल पहचान का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह फिटनेस, भागीदारी और रनिंग के जज्बे के उत्सव के रूप में पूरे शहर को एक साथ लाता है। कई मायनों में इसकी स्थायी विरासत एक फिट और स्वस्थ भारत के उस विजन को दर्शाती है, जिसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'स्वास्थ्य, फिटनेस, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और व्यापक सामाजिक-आर्थिक तथा परोपकारी प्रभाव पर केंद्रित वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बन गई है। प्रतिभागियों का उत्साह और खुशी वास्तव में प्रेरणादायक है और दिल्ली सरकार इस आयोजन के साथ मजबूती से खड़ी है, ताकि इसका यह संस्करण और भी सफल हो।'

पोखरण रेंज में वायु सेना के 'ड्रोनथॉन' ने दिखाई स्वदेशी ऑपरेशनल क्षमता

वायु सेना को भारत में विकसित हो रही नई टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन की बेहतर समझ मिली

नई दिल्ली। घरेलू उद्योग को अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (यूएएस) और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (सीयूएएस) में अपनी काबिलियत और तरक्की दिखाने के लिए भारतीय वायु सेना का 'आईएएफ ड्रोनथॉन' बुधवार को जैसलमेर के पोखरण रेंज में पूरा हुआ। नई ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ-साथ उनकी ऑपरेशनल क्षमता देखने और आपसी सीख को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए डिजाइन किये गए इस इवेंट ने दिखाया कि तकनीक को ऑपरेशनल क्षमता में कैसे बदला जा सकता है।

इस इवेंट में स्थिर प्रदर्शन और लाइव प्रदर्शन शामिल किये गए, जिससे आजकल के समाधान पहचानने और उनकी लड़ाई में असरदार होने का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इसमें सर्विलांस और टोही, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, झुंड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र पर ध्यान दिया गया।

'आत्मनिर्भर भारत' के राष्ट्रीय विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए ड्रोनथॉन-2026 का मकसद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, स्टार्ट-अप्स और इनोवेटर्स को जोड़कर स्वदेशी डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करना था, ताकि वायु सेना तकनीकी रूप से उन्नत, स्वदेशी और भविष्य के लिए तैयार फोर्स बनाने के लिए चुनौतियों का सामना कर सके।

भारतीय वायु सेना को तेजी से बदलते ऑपरेशनल माहौल में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए 'ड्रोनथॉन' भविष्य में इंडस्ट्री, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को एक साथ लाएगा, ताकि वे अनमैन्ड और काउंटर-अनमैन्ड सिस्टम में अपनी काबिलियत दिखा सकें। तीन दिन के इस इवेंट में वायु सेना सर्विलांस और टोही, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, स्वॉर्म टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया। ड्रोनाथॉन इवेंट वायु सेना की इंडस्ट्री पार्टनरशिप पर बढ़ती निर्भरता को दिखाता है, ताकि बिना ड्राइवर वाले सिस्टम में क्षमता विकास को तेज किया जा सके। डायरेक्टर जनरल (वेपन सिस्टम्स) एयर मार्शल प्रेमकुमार कृष्णस्वामी ने बताया कि ड्रोनथॉन-2026 सिर्फ तकनीकी प्रदर्शनी नहीं है बल्कि यह भारतीय वायु सेना की इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से सीधे जुड़ने की कोशिश है कि वे क्या डेवलप कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह देखने की कि ये प्लेटफ़ॉर्म असल ऑपरेशनल कंडीशन में कैसा परफॉर्म करते हैं।

जीटीबी अस्पताल में बनेगा 250 बेड का सुपर-स्पेशियलिटी कम ट्रॉमा ब्लॉक : रेखा गुप्ता

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में 250 बेड के सुपर-स्पेशियलिटी कम ट्रॉमा ब्लॉक के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 244.87 करोड़ रुपये होगी। यह स्वीकृति मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक दी गई। नया ब्लॉक जीटीबी अस्पताल के मौजूदा परिसर में ही बनाया जाएगा, इसलिए इसके लिए नई जमीन खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। यह ट्रॉमा ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) फेज-IV के अंतर्गत बनेगा।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि नए ब्लॉक के शुरू होने से गंभीर मरीजों को 24×7 इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा, जांच, सर्जरी और गहन चिकित्सा की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। उन्होंने बताया कि करीब 22,550 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाला यह ब्लॉक सात मंजिला होगा, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर छह मंजिलें होंगी। इसमें 250 बेड, 48 विशेषज्ञ ओपीडी कमरे और नौ आधुनिक ऑपरेशन थिएटर होंगे। बेसमेंट में ब्लड बैंक और प्रयोगशाला की व्यवस्था होगी। ग्राउंड फ्लोर पर 24×7 इमरजेंसी के साथ सीटी, एमआरआई और एक्स-रे जैसी जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि दूसरी मंजिल पर 72 बेड का आईसीयू होगा, जबकि चौथी और पांचवीं मंजिल पर 175 सामान्य व निजी वार्ड बेड होंगे। छठी मंजिल पर कार्यालय, कक्षाएं और डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए लैब बनाई जाएगी। कुल 250 बेड में 20 इमरजेंसी, 5 बर्न्स आईसीयू, 70 आईसीयू, 4 आइसोलेशन, 22 प्री-पोस्ट सर्जरी, 102 सामान्य वार्ड और 25 निजी कमरे के बेड शामिल होंगे। ब्लॉक में न्यूरो, हड्डी, त्वचा और दंत चिकित्सा सहित विभिन्न विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध होंगी। गंभीर मरीजों के लिए कुल 77 क्रिटिकल-केयर बेड की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए ब्लॉक में दुर्घटना और गंभीर आपातकालीन मामलों के लिए 24×7 ट्रॉमा उपचार की सुविधा होगी। मरीजों की जांच के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सर्जरी के लिए नौ आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा ब्लड स्टोरेज की पूरी सुविधा वाला ब्लड बैंक भी स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि गंभीर दुर्घटना के मामलों में समय पर उपचार बेहद महत्वपूर्ण होता है। नए ब्लॉक में इमरजेंसी से लेकर जांच, गहन चिकित्सा और सर्जरी तक की आवश्यक सुविधाओं को एकीकृत तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पूर्वी दिल्ली में गंभीर दुर्घटना और आपातकालीन मामलों के इलाज की क्षमता में विस्तार होगा। परियोजना की निगरानी के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति हर तीन महीने में बैठक कर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगी। अस्पताल को वर्ष 2028 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीटीबी अस्पताल में बनने वाला यह नया ब्लॉक पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए गंभीर दुर्घटना और आपातकालीन मामलों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करेगा। 250 नए बेड, 24×7 ट्रॉमा केयर, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक जांच सुविधाएं, विशेषज्ञ सेवाएं और ब्लड बैंक जैसी व्यवस्थाओं से अस्पताल की उपचार क्षमता मजबूत होगी।

मालवीय नगर अग्निकांड : हाई कोर्ट ने होटल मालिक लवकेश बजाज की मेडिकल रिपोर्ट मांगी

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज की स्वास्थ्य के आधार पर दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। उच्च न्यायालय जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 21 सितंबर को करेगा। लवकेश बजाज ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि लवकेश बजाज सर्जरी के लिए राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हुआ था जिसके बाद उसे डिस्चार्ज कर फिर से जेल भेज दिया गया। उसके बाद कोर्ट ने लवकेश बजाज की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया गया है।

जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भानु प्रताप सिंह ने तीन आरोपितों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने तीनों आरोपितों को 17 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। तीन सितंबर को साकेत कोर्ट ने लवकेश बजाज, होटल के मैनेजर जय मिश्रा और कुक केसर नेगी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। लवकेश बजाज और जय मिश्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं जबकि केसर नेगी को 27 जुलाई को जमानत मिली थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 01 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने

आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 326(जी), 324(5), 125 और 287 के तहत आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को 4 जून को और केसर नेगी को 6 जून को गिरफ्तार किया था। 8 जून को जय मिश्रा ने भी कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस के मुताबिक केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए और कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए। होटल में 2 कमरे थे। होटल से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था। होटल की खिड़कियों को स्थायी रुप से बंद कर दिया गया था और सेंसर संचालित मुख्य दरवाजा था। 03 जून को मालवीय नगर के होटल में सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लगी थी। इस हादसे में बेसमेंट में फंसे 22 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।

सत्य निकेतन घटना को लेकर अभाविप का कांग्रेस- एनएसयूआई पर हमला, कहा- विद्यार्थियों की समस्या का समाधान नहीं, मुद्दा चाहिए

नई दिल्ली। सत्य निकेतन की घटना और विद्यार्थियों के लिए 10 हजार क्षमता वाले छात्रावास के निर्माण की घोषणा को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने कांग्रेस-एनएसयूआई पर निशाना साधा। अभाविप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस-एनएसयूआई विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान चाहने के बजाय उन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना चाहती है। अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि सत्य निकेतन की घटना के समय मलबे पर हथौड़ा चलाकर रील बनाने से लेकर अब 10 हजार विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा पर सवाल उठाने तक कांग्रेस-एनएसयूआई लगातार विद्यार्थियों की समस्याओं पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जब छात्रावासों की कमी थी, तब कांग्रेस-एनएसयूआई इस विषय को लेकर राजनीति करती थी और अब जब विद्यार्थियों की मांग पर छात्रावास निर्माण की घोषणा हुई है, तो उसके निर्माण पर ही प्रश्न उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस-एनएसयूआई से स्पष्ट करने को कहा कि वह विद्यार्थियों की समस्या का समाधान चाहती है या केवल इस विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना चाहती है। सार्थक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद 50 से अधिक वर्षों तक दिल्ली में शासन किया है। कांग्रेस-एनएसयूआई को यह सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए कि इतने लंबे शासनकाल के दौरान विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और सुलभ छात्रावास उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए।

यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने काटे 2,511 चालान

नई दिल्ली। राजधानी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उत्तरी रेंज ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को बड़े स्तर पर कार्रवाई की। अलग-अलग इलाकों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 2511 चालान काटे। इनमें सबसे ज्यादा कार्रवाई सड़क किनारे गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ हुई। गलत पार्किंग के 2041 चालान काटे गए। पुलिस के मुताबिक, अभियान डीसीपी ट्रैफिक उत्तरी रेंज डॉ. सचिन कुमार सिंघल की निगरानी और निर्देशन में चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई की गई। सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़े करने से यातायात प्रभावित होने के साथ-साथ कई जगह जाम की स्थिति बनती है। इसी को देखते हुए गलत पार्किंग पर विशेष जोर दिया गया। अभियान के दौरान गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ऐसे वाहन चालकों के 383 चालान काटे गए। गलत दिशा

में वाहन चलाना सड़क हादसों की आशंका बढ़ाने के साथ दूसरे वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा करता है।

इसके अलावा वाहनों के शीशों पर नियमों के विपरीत टिंटेड ग्लास का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस तरह के 87 चालान किए। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, अभियान का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि सड़कों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर करना, कैरिजवे पर अनावश्यक अवरोध रोकना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए ट्रैफिक कर्मियों को संवेदनशील और ऐसे स्थानों पर लगातार मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं, जहां नियमों का उल्लंघन अधिक होता है। अधिकारियों ने कर्मचारियों को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा है। उत्तरी रेंज ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि सड़क पर यातायात अनुशासन बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

करणी सेना ने आरक्षण और यूजीसी नियमों के विरूद्ध प्रदर्शन की मांगी इजाजत, हाई कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ जंतर-मंतर पर 20 सितंबर को प्रदर्शन करने की इजाजत देने की मांग पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप याचिका में त्रुटि दूर कर लीजिए, याचिका अपने आप लिस्ट हो जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पहले तो 20 सितंबर को प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। तब कोर्ट ने कहा कि 20 सितंबर को प्रदर्शन है आपने याचिका दायर की है तो ये अपने आप लिस्ट हो जाएगी। इसके पहले उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वो जंतर-मंतर पर आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत देने पर 14 सितंबर तक फैसला ले। क्षत्रिय करणी सेना 20 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है। करणी सेना ने पहले 6 सितंबर को प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर को याचिकाकर्ता से कहा था कि आप प्रदर्शन की तिथि बदल लीजिए। 6 सितंबर की तिथि में खास क्या है। अगर पुलिस उस तारीख पर सहमत नहीं है तो आप दूसर तारीख रख लीजिए। याचिका करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत ने दायर की है। करणी सेना ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस को 27 अगस्त को पत्र लिखकर कहा गया था कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। 28 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने उनकी अर्जी ये कहते हुए नामंजूर कर दी थी कि ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारी चल रही है।

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर एनडीएमसी का 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम, एक लाख से अधिक दीपों से जगमगाएगी दिल्ली

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर के अवसर पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की ओर से 'सेवा माह' के तहत 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कर्तव्य पथ से सेवा तीर्थ तक एक लाख से अधिक मिट्टी के दीप प्रज्वलित किए जाएंगे।

एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बुधवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन में करीब 5,000 लाभार्थी, एनडीएमसी कर्मचारी, विद्यार्थी और शिक्षक भाग लेंगे। शाम 7 बजे एक साथ एक लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। चहल ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा, समर्पण, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना को दीप प्रज्वलन के माध्यम से अभिव्यक्त करना है। कार्यक्रम में आयुष्मान भारत, सुकन्या समृद्धि योजना और पीएम स्वनिधि समेत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल होंगे। दीपों के माध्यम से इन योजनाओं से जुड़े संदेश और आकृतियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिवस 'सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री के 25 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण उनकी सार्वजनिक यात्रा के प्रमुख विषय रहे हैं।

कार्यक्रम को 'विकसित भारत @2047' के विजन से जोड़ते हुए चहल ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में आधुनिक शहरी अधोसंरचना, बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं, हरित क्षेत्रों, स्वच्छता और स्मार्ट सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, भारत मंडपम, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे प्रमुख विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष ने बताया कि परिषद अपने क्षेत्र में स्वच्छता, हरित क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाओं, स्मार्ट सेवाओं और शहरी अधोसंरचना को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कार्य कर रही है। उन्होंने कर्मचारियों के हित में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए करीब 4,500 कर्मचारियों के नियमितीकरण को प्रमुख उपलब्धि बताया। चहल ने नागरिकों से भी 17 सितंबर की शाम 7 बजे अपने घरों में एक दीप प्रज्वलित कर 'आशीर्वाद का दीया' जनभागीदारी अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक दीप सेवा के नाम, एक दीप संकल्प के नाम और एक दीप राष्ट्र निर्माण के नाम।

पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत, बुलंदशहर से पति गिरफ्तार

नई दिल्ली। आनंद पर्वत इलाके की पंजाबी बस्ती में महिला (33) की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति चंद्रपाल भाटी (34) को बुलंदशहर (यूपी) से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में बेटी के बयान और मौके से मिले परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पति पर शक हुआ था। पूछताछ में आरोपित ने कथित तौर पर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था और वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण थे।

पुलिस के मुताबिक, 14 सितंबर को आनंद पर्वत थाने में महिला की हत्या की सूचना मिली थी। सूचना पर एसआई जितेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ पंजाबी बस्ती पहुंचे। वहां एक कमरे में महिला मृत हालत में मिली। वह अपने पति, दो नाबालिग बेटियों और मां के साथ रह रही थी। जांच के दौरान करीब 10 साल की बड़ी बेटी ने पुलिस को बताया कि तड़के करीब 3:45 से 4 बजे के बीच उसकी नींद खुली तो उसने पिता को मां के पास देखा। वह मां की सांस चेक कर रहे थे। इसके बाद पिता घर से बाहर चले गए। कुछ देर बाद बच्ची ने देखा कि मां कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी।

पुलिस के अनुसार, शव की जांच में शरीर पर कोई स्पष्ट बाहरी चोट नहीं मिली, हालांकि गर्दन के बाईं तरफ नाखून जैसे निशान थे। क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने मौके का निरीक्षण कर फोटोग्राफी और जरूरी साक्ष्य जुटाए। महिला को एलएचएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिवार को सौंप दिया गया। बेटी के बयान और मौके के हालात से पति की भूमिका संदिग्ध लगने पर आनंद पर्वत थाने में एफआईआर नंबर 517/2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। एसएचओ आनंद पर्वत ने एसआई जितेंद्र कुमार समेत पुलिस टीम को सक्रिय किया।

जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज के विरोधाभासी दावों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध-प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज के दावों की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस याचिका में कोई जनहित नहीं है। याचिका नितिन नरेश ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने खुद को मीडियाकर्मी बताया है। याचिका में कहा गया था कि मीडिया रिपोर्टों में लाठीचार्ज का दावा किया गया है, जबकि दिल्ली पुलिस इस दावे को खारिज करती है, इसलिए इसमें विरोधाभास है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों को साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि क्या दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों के आधिकारिक बयानों में कोई विरोधाभास है। हम ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं करेंगे, यहां हर तरह के मामले दायर किए जा रहे हैं। इसमें कोई जनहित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने 20 अगस्त को काकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। इस कमेटी में पूर्व जज जस्टिस रवि शंकर झा, पूर्व जज जस्टिस शलिंदर कौर, पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और पूर्व डीजीपी डॉ एल आर बिश्नोई शामिल हैं।

रोहिणी फायरिंग मामले में युवक गिरफ्तार

नई दिल्ली। रोहिणी के केएन काटजू मार्ग इलाके में युवक से झगड़े के बाद फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि दो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल देसी कट्टा और फायर किया हुआ कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान सेक्टर-26, रोहिणी निवासी शांतनु (18) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, उसका पहले भी लूट के दो मामलों में शामिल होना सामने आया है। पुलिस के अनुसार, 12 सितंबर को केएन काटजू मार्ग थाने में बंगाली बस्ती पुनर्वास कॉलोनी, सेक्टर-26 में फायरिंग की पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो शिकायतकर्ता ने बताया कि तीन युवकों ने उसके भांजे अर्जुन और उसके दोस्तों से झगड़ा किया। इसी दौरान आरोपितों में से एक ने कथित तौर पर गोली चला दी। मामले में एफआईआर नंबर 319/26, धारा 109, 125, 3(5) बीएनएस और 27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। मौके पर मोबाइल क्राइम टीम और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए और घटनास्थल की जांच की गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक टीम बनाई। एसीपी प्रशांत विहार आरपी मीणा की निगरानी में टीम ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना के आधार पर आरोपितों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को शांतनु के बारे में सुराग मिला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ दो नाबालिगों को भी पकड़ा गया। पुलिस ने उनके पास से वारदात में इस्तेमाल देसी कट्टा और फायर किया हुआ कारतूस बरामद किया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि शांतनु की अर्जुन से पहले से रंजिश थी। पुलिस के मुताबिक, इसी रंजिश के चलते विवाद हुआ और कथित तौर पर फायरिंग की गई। पुलिस मामले में हथियार के स्रोत और घटना में शामिल अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

डूसू चुनाव 2026-27 से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर डीयू कुलपति ने की बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 2026-27 के सुचारू रूप से संचालन हेतु विश्वविद्यालय अधिकारियों, कॉलेजों के प्रिंसिपलों, हॉल्स और हॉस्टलों के प्रोवोस्ट और पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई। डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने डूसू चुनाव की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही चुनाव को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि डूसू चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने चाहियें। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके शिक्षकों के लिए सभी विद्यार्थी बराबर हैं। कुलपति ने शिक्षकों से अपील की कि वे किसी भी तरह के पक्षपात से बचें। उन्होंने कहा कि डूसू चुनाव शांतिपूर्ण और ठीक-ठाक से हों, इसके लिए सभी संबंधित लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं।

प्रो. योगेश सिंह ने सभी प्रिंसिपलों से अपील की कि वे अपने-अपने कॉलेजों में अगले 3-4 दिनों तक सुरक्षा को बढ़ाए रखें। सभी कॉलेज अपने यहां एक-एक शिक्षक को नियुक्त करें, जोकि डूसू चुनाव प्रक्रिया के दौरान पुलिस के साथ लाइजनिंग का काम करें। कुलपति ने कहा कि चुनाव प्रबंधों में शिक्षकों की ज्यादा भागीदारी होने से चुनाव अच्छे से सम्पन्न होंगे।

इस अवसर पर डीन ऑफ कॉलेज प्रो. बलराम पाणी, साउथ कैंपस की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी, रजिस्ट्रार डॉ विकास गुप्ता, कल्चर काउंसिल के अध्यक्ष एवं पीआरओ अनूप लाठर, मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा, मुख्य रिटर्निंग अधिकारी डॉ. राजेश सिंह और दिल्ली पुलिस की ओर से कई अधिकारियों सहित डीयू के विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपल, विभागाध्यक्ष और विभिन्न छात्रावासों के प्रोवोस्ट व वार्डन आदि भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान बताया गया कि चुनाव से एक दिन पहले कॉलेजों को ईवीएम पहुंचाई जाएंगी। ईवीएम भेजने का काम सुबह आठ बजे शुरू होगा और इसके लिए तैनात मास्टर ट्रेनर इन्हें पहुंचाएंगे। डूसू चुनाव के लिए वोटिंग 18 सितंबर को होगी। वोटिंग का समय डे-क्लास के लिए सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर एक बजे तक और इवनिंग क्लास के लिए दोपहर तीन बजे से शाम साढ़े सात बजे तक है। वोटिंग के बाद, ईवीएम को छात्र प्रतिनिधियों और चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में उनके बक्सों में सील किया जाएगा और दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पस हॉल (यूनिवर्सिटी इंडोर स्टेडियम) में जमा किया जाएगा। वोटों की गिनती दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पस हॉल में 19 सितंबर को होगी। चुनाव के दौरान संवेदनशील जगहों पर हिंसा की किसी भी घटना को रोकने के लिए 18 सितंबर तक रात में गश्त जारी रहेगी। वोटिंग के दिन कॉलेजों एवं विभागों एवं संस्थानों के बाहर पुलिस गश्त का प्रबंध होगा। इसके अलावा, महिला कॉलेजों में महिला कॉन्स्टेबलों की तैनाती का भी इंतजाम होगा।

एक नजर

केशवपुरम इलाके में माचिस मांगने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या

नई दिल्ली। केशवपुरम इलाके में सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगने को लेकर हुए विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में उसके साथ मौजूद एक अन्य युवक भी घायल हो गया। पुलिस ने मामले में दो युवकों को गिरफ्तार करने के साथ एक नाबालिग को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान नरेश बहादुर उर्फ नेपाली (19) और तरुण (19) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, नरेश ने चाकू से भवानि और आशा राम पर हमला किया, जबकि तरुण और नाबालिग ने दोनों के साथ मारपीट की। मुख्य आरोपित की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल खून लगा चाकू बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार, मंगलवार को केशवपुरम थाने में चाकूबाजी की पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो डीएसआईआईडीसी शराब की दुकान के सामने फुटपाथ पर खून पड़ा मिला। जांच में पता चला कि दो घायल युवकों को दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल में भवानि (30) को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके शरीर के बाईं तरफ पीठ में गहरा घाव था। वहीं आशा राम (32) का इलाज चल रहा था। उसके बाईं तरफ सीने के निचले हिस्से में चाकू लगा था और वह बयान देने की स्थिति में नहीं था। जांच में पता चला कि भवानि और आशा राम का 2-3 युवकों से माचिस मांगने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस के मुताबिक, युवकों ने सिगरेट जलाने के लिए उनसे माचिस मांगी थी। माचिस नहीं देने पर कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि इसके बाद तीनों ने दोनों पर हमला कर दिया। इसी दौरान नरेश ने चाकू से दोनों पर वार किए। मामले में एफआईआर नंबर 321/26, धारा 103(1)/109(1) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया। मौके पर क्राइम टीम को बुलाकर जांच कराई गई और साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने नरेश और तरुण को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, नरेश की निशानदेही पर खून लगा चाकू बरामद हुआ। मामले में आगे की जांच जारी है।

पुलिस ने 12 करोड़ की कोकीन खेप पकड़ी, तीन विदेशी नागरिक गिरफ्तार

फरीदाबाद। नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद पुलिस और एनसीबी दिल्ली की संयुक्त टीम ने लकड़पुर में एक मकान पर छापा मारकर करीब 15 करोड़ रुपये कीमत के मादक पदार्थ बरामद किए। कार्रवाई के दौरान तीन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। बरामद सामान में 2.337 किलोग्राम कोकीन, 26 ग्राम एम्फेटामाइन और 1.378 किलोग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ शामिल है। इसके अलावा 50 हजार रुपये नकद भी बरामद हुए हैं।सहायक पुलिस अधीक्षक अपराध अमन यादव ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि क्राइम ब्रांच एनआईटी को थाना सूरजकुंड क्षेत्र के लक्कड़पुर में विदेशी नागरिकों के पास मादक पदार्थ होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर निरीक्षक अनिल छिल्लर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच एनआईटी और एनसीबी दिल्ली की टीम ने 15/16 सितंबर की रात तलाशी वारंट के साथ शिव दुर्गा बिहार स्थित मकान नंबर 16 की दूसरी मंजिल पर छापा मारा। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए। एनसीबी दिल्ली की टीम से कराई गई जांच में बरामद पदार्थों में कोकीन और एम्फेटामाइन की पुष्टि हुई। पुलिस के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है।पुलिस ने मौके से ईफायानी इम्युनुल, बेल जोन उर्फ अन्नूदून इम्युनुल निवासी नाइजीरिया और रैमी उर्फ ओमस ओवी निवासी कैमरून को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी मकान में किराये पर रह रहे थे। उनके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। मामले में थाना सूरजकुंड में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार मकान में अफ्रीकी देशों के 10 अन्य लोग भी किराये पर रह रहे थे।

फिनटेक कंपनी का सर्वर हैक कर 2 करोड़ 42 लाख की ठगी

नोएडा। नोएडा के साइबर क्राइम थाने में एक कंपनी के अधिकारी ने आज सुबह को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी कंपनी मोबाइल फोन रिचार्ज, बिल पेमेंट, आधार विड्रोल, डॉमेस्टिक मनी ट्रांसफर की सर्विस प्रोवाइड कराती है। उनके अनुसार 13 सितंबर को अज्ञात बदमाशों ने उनकी कंपनी का सर्वर हैक कर लिया तथा उनकी कंपनी के एपीआई पोर्टल को हैक करके दो करोड़ 42 लाख 62 हजार 576 रूपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिया है। पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने बताया कि आज सुबह को राजकुमार पुत्र अनिल कुमार ने थाना साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सेक्टर 65 के बी- ब्लॉक में उनकी कंपनी है। उनकी कंपनी रिनोवा पेटेक प्राइवेट लिमिटेड एक फिनटेक कंपनी है, जिसमें वे लोग मोबाइल फोन का रिचार्ज, बिल पेमेंट, आधार विड्रोल, डॉमेस्टिक मनी ट्रांसफर की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। उनके अनुसार 13 सितंबर दोपहर बाद से शाम 8 बजे के बीच उनकी कंपनी का सर्वर अज्ञात साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया, तथा एपीआई पोर्टल के माध्यम से उनकी कंपनी से 2 करोड़ 42 लाख 65 हजार 576 रूपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिया। यह पैसा 497 ट्रांजैक्शन के माध्यम से 28 बैंकों के 58 अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है।

हीरो फिनकॉर्प के कॉरपोरेट खाते से 12.84 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर समेत पांच गिरफ्तार

नई दिल्ली,एजेंसी। हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के कॉरपोरेट बैंक खाते से 12.84 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले का स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने खुलासा किया है। साइबर अपराधियों ने कंपनी की जानकारी और अनुमति के बिना 317 डिजिटल लेनदेन के जरिए 12,84,09,997 रुपये 34 अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिए। मामले में पुलिस ने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर समेत पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जांच में टेलीग्राम के जरिए चीन से जुड़े साइबर समूहों के संपर्क और ठगी की रकम को यूएसडीटी में बदलकर विदेश भेजे जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने ठगी की रकम में से करीब 1.70 करोड़ रुपये विभिन्न बैंक खातों में होल्ड कराए हैं।

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड की शिकायत पर 21 अगस्त को स्पेशल सेल थाने में प्राथमिकी संख्या 135/26 दर्ज की गई थी। कंपनी को एचडीएफसी बैंक के सिस्टम अलर्ट से कॉरपोरेट खाते से लगातार हो रहे अनधिकृत लेनदेन की जानकारी मिली थी। कंपनी प्रबंधन ने किसी भी भुगतान या रकम हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी थी। मामले की जांच के लिए आईएफएसओ के एसीपी प्रेम चंद्र खंडूरी की देखरेख और डीसीपी गौरव त्यागी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने संदिग्ध बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल लेनदेन से जुड़े तकनीकी विवरणों का विश्लेषण किया। इसके बाद विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर निवासी अभय कुमार सोलंकी के बैंक खाते में ठगी की 60 हजार रुपये की रकम आई थी। पुलिस के अनुसार उसने यह रकम एटीएम से निकाल ली थी। कुरुक्षेत्र निवासी 26 वर्षीय लवली के नाम पर प्रॉपर्टी गैलरी का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, थानेसर स्थित खाता है। इस खाते में ठगी की करीब 80 लाख रुपये की रकम पहुंची। पुलिस के मुताबिक, लवली ने कैथल के चीका निवासी सत्याम के कहने और लालच में यह खाता खुलवाया था। सत्याम फिलहाल फरार है।

जयपुर निवासी नमन कुमार के नाम पर इंफर्मिटी सर्विसेज का यस बैंक खाता है, जिसमें करीब 40 लाख रुपये आए। उसने अपना इंडसइंड बैंक खाता भी उपलब्ध कराया था, जिसमें करीब 70 लाख रुपये जमा हुए। जांच में यह खाता देशभर में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज 43 शिकायतों से जुड़ा मिला। पुलिस के अनुसार नमन की मुलाकात विकास के माध्यम से हरमन से हुई थी। हरमन ने उसके मोबाइल में एपीके फाइल इंस्टॉल कराकर बैंक खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम प्राप्त करने और आगे स्थानांतरित करने के लिए किया। नमन दिल्ली आकर कृष्णा नगर स्थित होटल निर्वाण रेजीडेंसी में भी ठहरा था, जहां इसी तरीके से उसके यस बैंक खाते का संचालन किया गया। राजस्थान के बीकानेर निवासी 24 वर्षीय हरमन के संपर्क में टेलीग्राम पर कई चीनी समूह थे। वह उदयपुर निवासी देवेंद्र सिंह चौहान के संपर्क में भी था। पुलिस के मुताबिक, देवेंद्र टेलीग्राम के माध्यम से ठगी की रकम को यूएसडीटी में परिवर्तित करता था। इसके बाद रकम विदेश में मौजूद साइबर अपराधियों तक पहुंचाई जाती थी। जांच के अनुसार हरमन ने कमीशन के आधार पर नमन का बैंक खाता हासिल कर उसका संचालन किया। इसके बदले उसे देवेंद्र से करीब 1.50 लाख रुपये कमीशन मिला। जयपुर निवासी विकास (30) आरबीएल बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर है। पुलिस के मुताबिक, उसने नमन को यस बैंक और इंडसइंड बैंक में खाते खुलवाने में मदद की और उसकी मुलाकात हरमन से कराई।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने मेगा रक्तदान शिविर की तैयारियों का किया निरीक्षण

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन (17 सितंबर) को त्यागराज स्टेडियम में आयोजित होने वाले मेगा रक्तदान शिविर की तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों, सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जरूरी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। मंत्री ने रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग, ब्लड कलेक्शन, मेडिकल सहायता, सुरक्षा, एम्बुलेंस सेवाओं, साफ-सफाई, भीड़ प्रबंधन और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के लिए की जा रही तैयारियों का खुद मौके पर जाकर जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली के नागरिकों में मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है और हमें पूरा भरोसा है कि बड़ी संख्या में दिल्ली के नागरिक आगे आएंगे और रक्तदान शिविर में हिस्सा लेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस मेगा रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ें और रक्तदान शिविर शुरू होने से पहले सभी जरूरी इंतजाम गुणवत्तापूर्ण मानकों के अनुसार वक्त से पहले पूरे कर लिए जाएं। मंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ हर ब्लड डोनर के लिए सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आपसी तालमेल बढ़ाने के साथ सार्थक प्रयास किए जाएं।

दिल्ली को बिन-मुक्त बनाने की तैयारी, तीन जोन में तीन माह के भीतर शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

नई दिल्ली। दिल्ली में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एमसीडी ने अब पारंपरिक सामुदायिक कूड़ेदानों पर निर्भरता कम कर शहर को बड़े पैमाने पर बिन-मुक्त बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। निगमायुक्त संजीव खिरवार ने बुधवार को स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को वार्डवार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में स्रोत पर कचरा पृथक्करण, जोनवार स्वच्छता योजनाओं, कूड़ा संवेदनशील बिंदुओं (जीवीपी), द्वितीयक संग्रहण केंद्रों के आसपास सफाई, कचरा संग्रहण एवं परिवहन तथा विकेंद्रीकृत कचरा प्रसंस्करण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

निगमायुक्त ने सभी जोनल उपायुक्तों को प्रत्येक वार्ड में मौजूदा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का आकलन कर वार्डवार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके तहत करीब 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में ऐसी उपयुक्त भूमि और सुविधाओं की पहचान की जाएगी, जहां गीले एवं जैव अपघटनीय कचरे के विकेंद्रीकृत उपचार के लिए सीबीजी, बायोगैस, कंपोस्टिंग और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सके। आरडब्ल्यूए और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के साथ-साथ अधिकृत-अनधिकृत कॉलोनियों, संकरी एवं भीड़भाड़ वाली गलियों, जेजे क्लस्टर, अस्पतालों, बाजारों, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों की जरूरत के मुताबिक अलग-अलग कचरा संग्रहण मॉडल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे इलाकों में जहां बड़े पारंपरिक कचरा संग्रहण वाहन नहीं पहुंच सकते, एमसीडी उपयुक्त मार्गों की पहचान कर छोटे या विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहनों को तैनात करेगी। इसका उद्देश्य घर-घर कचरा संग्रहण को प्रभावी बनाना और सड़क किनारे कचरा जमा होने अथवा द्वितीयक डंपिंग को रोकना है। सामुदायिक कूड़ेदानों पर निर्भरता को भी चरणबद्ध तरीके से कम करने की योजना है। निगमायुक्त ने इसे मौजूदा स्तर के अधिकतम 20 प्रतिशत तक लाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। इसके लिए तीन जोन में तीन माह के भीतर पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। बाजारों को भी निर्धारित संग्रहण व्यवस्था और समर्पित परिवहन प्रोटोकॉल के जरिए चरणबद्ध तरीके से बिन-मुक्त किया जाएगा।

सीएक्यूएम के आदेश की धज्जियां, गाजियाबाद में दौड़ रहीं 300 से अधिक खटारा बसें

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

साहिबाबाद। अक्टूबर में सर्दी शुरू होने के साथ ही प्रदूषण का वार फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि गाजियाबाद के लोगों को वर्षभर ही साफ हवा नहीं मिल पाती। फिर भी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश के तीन वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने गाजियाबाद रीजन में अभी तक 300 से अधिक बीएस-तीन व चार बसों को नहीं बदल सका। एनसीआर में प्रतिबंध के बाद भी इनमें से ज्यादातर बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे इन बसों से प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। सीएक्यूएम ने एनसीआर में प्रदूषण का बड़ा कारण पुराने वाहनों के संचालन को भी माना था।

इनमें रोडवेज की बीएस-3 व 4 बसें भी शामिल हैं। इसकी रोकथाम के लिए आयोग ने बसों को बंद करने के लिए परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ अक्टूबर 2023 में बैठक की थी। इन बसों को एनसीआर में बंद करने का फैसला लिया गया था। इनके स्थान पर बीएस-छह, सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना था, लेकिन परिवहन निगम के अधिकारियों ने सीएक्यूएम से अनुमति लेकर वर्ष 2024 में बसों का संचालन गया था। इसके बाद वर्ष 2025 में सर्दी के दौरान प्रदूषण बढ़ने पर बसों पर रोक लगी तो रूट बदल दिए, लेकिन इस साल भी बसों को नहीं बदला जा सका। अक्टूबर शुरू होने के साथ ही प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाएगा और ग्रेप की पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएंगी। इससे इन बसों का संचालन एनसीआर में पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि परिवहन निगम को डिमांड भेजी गई है। ग्रेप लागू होने पर बसों का रूट बदल दिया जाएगा। एनसीआर के बाहर के रूटों पर ही संचालन किया जाएगा। तीन वर्ष पहले परिवहन निगम के बेड़े में करीब 500 बीएस-तीन व चार बसें थीं। बीते करीब दो वर्ष में 210 बसों को बदला गया है। इनके स्थान पर बीएस-छह बसों को शामिल किया गया है। इनमें से बड़ी संख्या में बसों को नीलाम किया जा चुका है। बची हुई बसों को भी नीलाम किया जाएगा। बीएस-3 व 4 बसों के संचालन पर आठ नवंबर 2023 को ही रोक लग चुकी है। वहां केवल बीएस-6 बसों को भेजा जा रहा है, जो बसें दिल्ली के आनंद विहार से संचालित होती थीं उन बसों को कौशांबी डिपो शिफ्ट कर दिया गया था। यहीं से इन बसों का संचालन किया जा रहा है। बीएस (भारत स्टेज) प्रदूषण मापक पैमाना है। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तय करता है। ये वाहनों से उत्सर्जित होने वाले कार्बन का पर्यावरण और लोगों के सेहत पर पड़ रहा असर जांचता है और उसके अनुसार वाहन के स्तर को निर्धारित करता है। बीएस नंबर वाहनों के इंजन का प्रदूषण नियंत्रण का स्तर बताता है।

एमसीडी नेता सदन जय भगवान यादव ने नजफगढ़ जोन के नंगली डेयरी का किया निरीक्षण

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली नगर निगम में सदन के नेता जय भगवान यादव ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के तहत बुधवार को नजफगढ़ ज़ोन के नंगली डेयरी (वार्ड संख्या 124) में स्वच्छता का निरीक्षण किया और क्षेत्र में नागरिक समस्याओं का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने डेयरियों, गलियों एवं सड़कों के आसपास अतिक्रमण तथा निगम प्राथमिक विद्यालय का भी गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों ने नंगली डेयरी की गलियों में गंदगी और सड़कों की खराब स्थिति के बारे में यादव को बताया। लोगों ने मृत पशुओं को तत्काल उठाने की समस्या से भी उन्हें अवगत कराया। मामले की गंभीरता पर संज्ञान लेते हुए जय भगवान यादव ने अधिकारियों को मृत पशुओं को तत्काल उठाने, इलाके की टूटी हुई कच्ची नालियों को पक्का करने और सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

यादव ने अधिकारियों को सड़कों के आसपास किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करने और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर इसकी निगरानी करने के भी निर्देश दिए। नेता सदन यादव ने अधिकारियों को नंगली डेयरी क्षेत्र में गोबर का समय पर निपटान और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी और आवश्यक मानव संसाधन तैनात करने का उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया। नेता सदन ने नंगली डेयरी स्थित निगम प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया और बच्चों के लिए पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए कहा। इस अवसर पर उनके साथ नजफगढ़ जोन के अध्यक्ष जयवीर सिंह राणा, उपाध्यक्ष सुषमा राठी, वार्ड 124 से पार्षद सविता, नजफगढ़ ज़ोन के उपायुक्त शशि प्रताप सिंह एवं सहायक आयुक्त सहित ज़ोन के विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

साइबर ठगी मामले में खाताधारक सहित तीन गिरफ्तार

फरीदाबाद। साइबर ठगी के मामलों में संलिप्त आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने एक मामले में खाताधारक सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान राजस्थान निवासी नेमाराम, मुदित पारिक तथा मुकेश जाखड़ के रूप में हुई है। पुलिस प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि साइबर थाना बल्लभगढ़ क्षेत्र में फोन हैक होने के बाद बैंक खाते से 60 हजार रुपये की अनाधिकृत निकासी का मामला सामने आया था। गांव तिगांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका मोबाइल फोन अचानक हैक हो गया तथा 31 अगस्त 2026 को उसके बैंक खाते से उसकी जानकारी के बिना 60 हजार रुपये कट गए। शिकायत के आधार पर साइबर थाना बल्लभगढ़ में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपित मुदित पारिक खाताधारक है, जिसके खाते में साइबर ठगी के 60 हजार रुपये ट्रांसफर हुए थे।

मंत्री सूद ने दिल्ली को 'सोलर कैपिटल' बनाने का किया आह्वान

नई दिल्ली। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को सोलर वेंडर्स और संबंधित हितधारकों का आह्वान किया कि वे दिल्ली सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी को देश की 'सोलर कैपिटल' बनाने के लक्ष्य में सहभागी बनें। उन्होंने 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के संबंध में आयोजित सोलर वेंडर्स मीट को संबोधित करते हुए दिल्ली में सौर ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देने के लिए व्यापक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की।

मंत्री सूद ने कहा की हम दिल्ली को भारत की 'सोलर कैपिटल' बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस 'स्केल और स्पीड' के साथ काम करते हैं, हम भी उनके अनुयायी हैं और उसी गति से काम करने का प्रयास करेंगे। हम इस परियोजना को अधिक से अधिक गति और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने सोलर वेंडर्स और उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार सौर ऊर्जा को अपनाने की प्रक्रिया में आने वाली पारंपरिक बाधाओं को दूर करने और उपभोक्ताओं एवं व्यवसायों के लिए प्रक्रिया को अधिक सरल एवं सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भी अग्रिम भुगतान करने में हिचकिचाते हैं। इसलिए सरकार ने आपके और उपभोक्ता के बीच इस बाधा को दूर कर दिया है। हम पूरी राशि का भुगतान करेंगे। सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही है।

सूद ने बताया कि योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा एक समर्पित पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया है। उन्होंने सोलर वेंडर्स से अपील की कि वे योजना के क्रियान्वयन को और अधिक पारदर्शी, सुगम एवं तेज बनाने के लिए अपने सुझाव और रचनात्मक फीडबैक सरकार के साथ साझा करें। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास इस परियोजना को बेहतर तरीके से, अधिक सुगमता के साथ और अधिक गति से लागू करने के लिए कोई सुझाव है, तो आपका स्वागत है। सौर ऊर्जा के विस्तार के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार आने वाले महीनों में लगभग 2.30 लाख सोलर पैनल इंस्टॉलेशन को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रही है।

एकेडमिक दबाव के चलते दसवीं की छात्रा ने 15वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र की गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी ने बीती रात को 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिया। वह दसवीं की छात्रा थी। घटना से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को अस्पताल मैं भर्ती करवाया। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मौके से आधे पेज का सुसाइड नोट मिला है। इसमें छात्रा ने पढ़ाई के दबाव से परेशान होने की बात लिखी है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि मंगलवार रात को डायल-112 के जरिये विजयनगर पुलिस को गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में एक छात्रा के 15वीं मंजिल से गिरने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा की पहचान 16 वर्षीय शनाया बिष्ट पुत्री देवेंद्र सिंह के रूप में हुई। वह इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल में दसवीं की छात्रा थी। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आत्महत्या करने की आशंका है। मौके से मिले आधे पेज के सुसाइड नोट में छात्रा ने एकेडमिक प्रेशर यानी पढ़ाई के दबाव से परेशान होने की बात लिखी है। पुलिस सुसाइड नोट की जांच कर रही है।

इसके साथ ही छात्रा के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना से पहले की परिस्थितियों की जानकारी मिल सके। एसीपी ने बताया कि मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि छात्रा किन परिस्थितियों में 15वीं मंजिल से गिरी। सोसाइटी में भी घटना से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। छात्रा के परिजनों से पूछताछ और मौके से मिले सुसाइड नोट की जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विहिप ने अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी का लोगो किया जारी

नई दिल्ली। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर उनके जीवन, कार्यों और सांस्कृतिक योगदान को स्मरण करने के लिए विशेष लोगो जारी किया। इस लोगो को जारी करते हुए विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महा-मंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने कहा यह लोगो उनके आध्यात्मिक संस्कारों, हिंदू समाज के गौरव-जागरण तथा भारतीय संस्कृति के प्रति आजीवन समर्पण को अभिव्यक्त करता है।

उन्होंने कहा कि लोगो में अंकित अशोक सिंघल नाम श्रद्धा और सम्मान का भाव प्रकट करता है, जबकि 'जन्म शताब्दी वर्ष 1926-2015' उनके जीवन-काल को रेखांकित करता है। 27 सितंबर को उनके जन्म के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जारी यह लोगो उनके विचारों, संकल्पों और कार्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने बताया कि लोगो की भगवा-केसरिया पृष्ठभूमि त्याग, तपस्या, आध्यात्मिक चेतना, शौर्य और राष्ट्रधर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। चारों ओर बना स्वर्णिम वलय भारतीय ज्ञान-परंपरा की शाश्वतता, गौरव और प्रकाश को दर्शाता है। लोगो में अंकित श्रीराम मंदिर श्रद्धेय अशोक सिंघल के जीवन के एक बड़े ध्येय तथा श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में उनके ऐतिहासिक योगदान का प्रतीक है। मंदिर के साथ लहराता भगवा ध्वज सनातन परंपरा, संगठन, त्याग और सांस्कृतिक स्वाभिमान का भाव प्रकट करता है। विहिप महामंत्री ने कहा कि लोगो के केंद्र में स्थित अशोक सिंघल का शांत, तेजस्वी और सौम्य व्यक्तित्व उनके आध्यात्मिक संस्कार, दृढ़ संकल्प, संगठन-कौशल तथा पूज्य संतों के प्रति श्रद्धा और हिंदू समाज के प्रति उनकी आत्मीयता को दर्शाता है। उनका तिलक और श्वेत वस्त्र सादगी, आध्यात्मिक आस्था और भारतीय जीवन-मूल्यों के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। नाम को उभारता गहरा लाल-मरून पट्ट ऊर्जा, साहस, संकल्प और संघर्षशीलता का भाव व्यक्त करता है, जबकि नीचे का पीताभ-स्वर्णिम आधार ज्ञान, प्रकाश, मंगल और भविष्य के प्रति आशा का संदेश देता है। बागड़ा ने बताया कि यह लोगो केवल एक दृश्य-चिह्न नहीं, बल्कि अशोक सिंघल के जीवन-संदेश का प्रतीकात्मक संकलन है।

आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में निर्णायक शिकंजा

कांतिलाल मांडोत

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। घाटी में आतंकवाद को केवल बंदूक उठाने वाले आतंकियों तक सीमित मानने के बजाय उनके पूरे सहयोगी तंत्र को निशाना बनाया जा रहा है। इसी रणनीति के तहत रविवार को काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के नेतृत्व में कुलगाम और शोपियां सहित कई इलाकों में संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। शोपियां के नादिगाम क्षेत्र में दिवंगत गुलाम हसन गनी के बेटे इरफान अहमद गनी के मकान पर भी सुरक्षा एजेंसियों ने दबिश दी। इस कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े संवेदनशील मामले की कड़ियों को जोड़ना और उसके पीछे सक्रिय नेटवर्क की पहचान करना बताया गया है।

कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब उस दौर से आगे बढ़ चुकी है, जिसमें केवल किसी हमले के बाद आतंकियों की तलाश की जाती थी। सुरक्षा एजेंसियां अब आतंकवाद की पूरी संरचना को समझकर उस पर एक साथ प्रहार कर रही हैं। आतंकवादियों को हथियार उपलब्ध कराने वालों से लेकर उन्हें सुरक्षित ठिकाना देने वालों, आर्थिक मदद पहुंचाने वालों और सीमा पार बैठे आकाओं के निर्देशों को जमीन पर लागू करने वाले स्थानीय सहयोगियों तक जांच का दायरा बढ़ाया गया है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में तलाशी और गिरफ्तारी की कार्रवाई लगातार दिखाई दे रही है। शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी सीमा पार आतंकी साजिश के मामले में कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला और सोपोर सहित दस स्थानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसियों के अनुसार इस मामले की कड़ियां पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आकाओं और घाटी में सक्रिय उनके स्थानीय सहयोगी तंत्र से जुड़ी हुई हैं। ये स्थानीय सहयोगी आतंकवादियों को घुसपैठ के बाद रसद, हथियार और दूसरी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में भूमिका निभाते हैं। ऐसे नेटवर्क को समाप्त करना आतंकवाद के खिलाफ स्थायी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। आतंकवाद की चुनौती को समझने के लिए कश्मीर की भौगोलिक और सामरिक स्थिति को भी देखना होगा। जम्मू-कश्मीर लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का सामना करता आया है। नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास की संवेदनशील परिस्थितियों का फायदा उठाकर आतंकवादी संगठनों ने समय-समय पर घुसपैठ की कोशिश की है। सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों के लिए स्थानीय सहयोगी नेटवर्क किसी भी साजिश को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदा रणनीति में इन सहयोगियों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इस पूरे अभियान में स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। किसी भी आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए केवल केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती। स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और जमीन पर उपलब्ध सूचनाओं का सही इस्तेमाल अभियान की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाता है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल से आतंकवादियों और उनके मददगारों तक पहुंचने में सुरक्षा एजेंसियों को सहायता मिल रही है।

इस मामले में 31 मार्च 2026 को एक नाके पर लश्कर से जुड़े एक ओवर ग्राउंड वर्कर की गिरफ्तारी के बाद जांच को महत्वपूर्ण दिशा मिली थी। उसके कब्जे से हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद किए गए थे। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क की कड़ियों को तलाशने का सिलसिला तेज हुआ। किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उससे जुड़े संपर्कों, वित्तीय गतिविधियों, हथियारों की आपूर्ति और दूसरे सहयोगियों की जानकारी सामने आना जांच का स्वाभाविक हिस्सा है। इसी आधार पर अब अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सुरक्षा एजेंसियां अब आतंकवाद के पारंपरिक ढांचे के साथ-साथ उसके नए तरीकों पर भी नजर रख रही हैं। आतंकवादी संगठनों की कोशिश रहती है कि स्थानीय स्तर पर ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाए जो सीधे हथियार उठाए बिना आतंकियों की सहायता करता रहे। यही नेटवर्क आतंकवादियों के लिए सूचना, आवागमन, ठिकाने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकता है। ऐसे तंत्र को कमजोर करने से आतंकवादियों की गतिविधियों पर सीधा असर पड़ता है। सरकार की ओर से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में संरक्षण या सहायता देने वालों के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदा कार्रवाई इसी नीति को जमीन पर लागू करने की दिशा में दिखाई देती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल मुठभेड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके आर्थिक, सामाजिक और संगठनात्मक आधार को कमजोर करना भी उतना ही जरूरी है। कश्मीर में पिछले वर्षों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ आतंकवादी नेटवर्क पर दबाव बढ़ा है। हालांकि चुनौती पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देने की कोशिशें अभी भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय हैं। ऐसे में खुफिया तंत्र को मजबूत करना, सीमा सुरक्षा को प्रभावी बनाना और स्थानीय स्तर पर संदिग्ध नेटवर्क की पहचान करना लगातार आवश्यक बना रहेगा। कश्मीर के आम नागरिकों के लिए भी आतंकवाद के खिलाफ यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है। लंबे समय से हिंसा और अस्थिरता का सबसे बड़ा नुकसान सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ा है। आतंकवाद का असर शिक्षा, रोजगार, व्यापार, पर्यटन और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। जब सुरक्षा वातावरण मजबूत होता है तो सामान्य जीवन को गति मिलती है और विकास की गतिविधियां भी तेजी से आगे बढ़ती हैं। इसलिए आतंकवाद के नेटवर्क को कमजोर करना केवल सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। कुलगाम और शोपियां में हुई ताजा छापेमारी इस व्यापक रणनीति का हिस्सा है। जांच एजेंसियां आतंकवाद की प्रत्येक कड़ी को तलाश रही हैं और सीमा पार से संचालित साजिशों तथा स्थानीय सहयोगी नेटवर्क के बीच संबंधों की जांच कर रही हैं। आने वाले दिनों में इन तलाशी अभियानों से और तथ्य सामने आ सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह प्रमाण आधारित और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप आगे बढ़े। जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति का रास्ता आतंकवाद के कमजोर होने से ही मजबूत होगा। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता, स्थानीय पुलिस की सक्रियता और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति मिलकर आतंकवाद के उस तंत्र को चुनौती दे रही है, जो वर्षों से घाटी की शांति को नुकसान पहुंचाता रहा है। अब लड़ाई केवल आतंकियों को पकड़ने की नहीं, बल्कि आतंकवाद को पैदा करने वाले पूरे नेटवर्क को समाप्त करने की है। यही रणनीति कश्मीर में स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास की नींव को और मजबूत कर सकती है।

भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए बहुभाषी एआई तकनीक भी विशेष महत्व रखती है। यदि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और प्रारंभिक सहायता केवल अंग्रेजी या कुछ सीमित भाषाओं तक रहेगी, तो बड़ी आबादी इससे बाहर रह जाएगी। भाषा-तकनीक और भारतीय भाषाओं के लिए विकसित डिजिटल प्रणालियां इस अंतर को कम कर सकती हैं। भविष्य में ऐसी सेवाओं को टेली-मानस जैसी सरकारी मानसिक स्वास्थ्य पहलों के साथ जोड़कर दूरदराज के क्षेत्रों तक प्रारंभिक सहायता पहुंचाई जा सकती है। व्यक्तिगत सहायता भी एआई की एक उपयोगी विशेषता हो सकती है। दवा लेने की याद दिलाना, नींद और दिनचर्या पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना, तनाव कम करने के अभ्यास सुझाना या संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा आधारित संरचित स्व-सहायता गतिविधियों में मार्गदर्शन देना कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां एआई सहयोगी भूमिका निभा सकता है। चिकित्सकों के लिए भी एआई मरीजों की नियमित निगरानी, जोखिम वाले मामलों की पहचान और प्राथमिकता तय करने में सहायक हो सकता है। इससे सीमित मानव संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव हो सकता है। लेकिन अवसरों के साथ जोखिम भी गंभीर हैं। भावनात्मक संकट में व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील स्थिति में होता है।

मानसिक स्वास्थ्य की पहली चौखट बनता एआई

डॉ. प्रियंका सौरभ

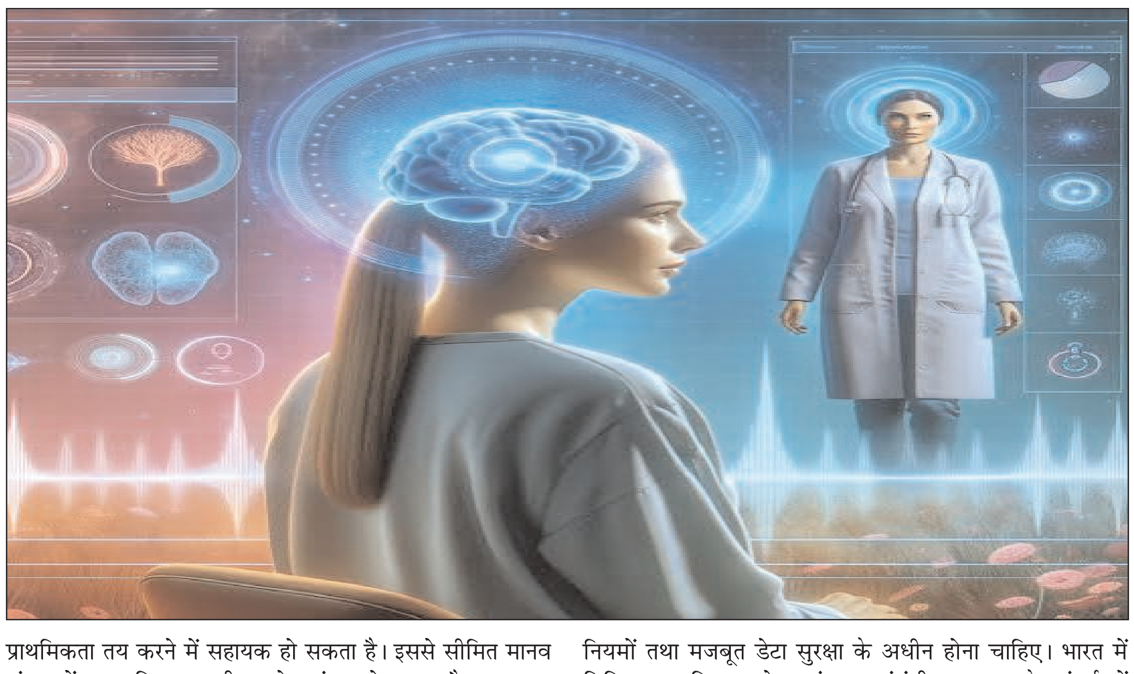

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के बीच अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित चैटबॉट लोगों के लिए तेजी से संपर्क का पहला माध्यम बनते जा रहे हैं। अकेलापन, चिंता, तनाव, अवसाद, रिश्तों की उलझन या भावनात्मक संकट के क्षणों में कई लोग पहले किसी चिकित्सक के पास जाने के बजाय एआई से बातचीत करना पसंद कर रहे हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अभी भी असमान है, एआई तकनीक एक नई संभावना प्रस्तुत करती है। हालांकि, यह समझना आवश्यक है कि एआई मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने का माध्यम हो सकता है, उनका विकल्प नहीं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे बड़ी चुनौतियों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की सीमित उपलब्धता, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सेवाओं का अभाव, उपचार की लागत तथा मानसिक बीमारी से जुड़ा सामाजिक कलंक शामिल हैं। ऐसे वातावरण में एआई की चौबीसों घंटे उपलब्धता महत्वपूर्ण अवसर पैदा करती है। व्यक्ति जब चाहे अपनी समस्या साझा कर सकता है और प्रारंभिक स्तर पर जानकारी, भावनात्मक सहारा तथा स्व-सहायता संबंधी सुझाव प्राप्त कर सकता है। एआई आधारित डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म इस दिशा में उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति सामाजिक झिझक भी एआई के उपयोग को बढ़ावा दे सकती है। अनेक लोग परिवार, मित्र या चिकित्सक के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने में संकोच करते हैं। अपेक्षाकृत गुमनाम डिजिटल बातचीत उन्हें अपनी चिंता, डर और परेशानियों को शब्द देने का अवसर देती है। इस प्रकार चैटबॉट मानसिक स्वास्थ्य संबंधी संवाद की पहली सीढ़ी बन सकते हैं और व्यक्ति को आवश्यकता होने पर आगे पेशेवर सहायता लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एआई का एक महत्वपूर्ण लाभ शुरुआती स्क्रीनिंग में भी है। व्यक्ति के संवाद, व्यवहार और कुछ डिजिटल संकेतों का विश्लेषण करके एआई संभावित चिंता, अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की पहचान में सहायता कर सकता है। हालांकि ऐसी स्क्रीनिंग को अंतिम चिकित्सकीय निदान नहीं माना जाना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल संभावित जोखिम को पहचानकर व्यक्ति को उचित विशेषज्ञ तक पहुंचाने में सहायता करना होना चाहिए। भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए बहुभाषी एआई तकनीक भी विशेष महत्व रखती है। यदि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और प्रारंभिक सहायता केवल अंग्रेजी या कुछ सीमित भाषाओं तक रहेगी, तो बड़ी आबादी इससे बाहर रह जाएगी। भाषा-तकनीक और भारतीय भाषाओं के लिए विकसित डिजिटल प्रणालियां इस अंतर को कम कर सकती हैं। भविष्य में ऐसी सेवाओं को टेली-मानस जैसी सरकारी मानसिक स्वास्थ्य पहलों के साथ जोड़कर दूरदराज के क्षेत्रों तक प्रारंभिक सहायता पहुंचाई जा सकती है। व्यक्तिगत सहायता भी एआई की एक उपयोगी विशेषता हो सकती है। दवा लेने की याद दिलाना, नींद और दिनचर्या पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना, तनाव कम करने के अभ्यास सुझाना या संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा आधारित संरचित स्व-सहायता गतिविधियों में मार्गदर्शन देना कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां एआई सहयोगी भूमिका निभा सकता है। चिकित्सकों के लिए भी एआई मरीजों की नियमित निगरानी, जोखिम वाले मामलों की पहचान और प्राथमिकता तय करने में सहायक हो सकता है। इससे सीमित मानव संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव हो सकता है।

लेकिन अवसरों के साथ जोखिम भी गंभीर हैं। भावनात्मक संकट में व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील स्थिति में होता है। यदि एआई गलत, अधूरी या संदर्भहीन जानकारी देता है तो वह व्यक्ति की समस्या को और बढ़ा सकता है। किसी नकारात्मक या भ्रमपूर्ण धारणा को चुनौती देने के बजाय चैटबॉट अनजाने में उसे मजबूत कर दे, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यही कारण है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े एआई सिस्टम में सामान्य सूचना देने वाले चैटबॉट और चिकित्सकीय सहायता देने वाले प्रमाणित उपकरणों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब व्यक्ति एआई को वास्तविक चिकित्सक का विकल्प समझने लगता है। लगातार बातचीत के कारण भावनात्मक निर्भरता भी विकसित हो सकती है। व्यक्ति यह मान सकता है कि मशीन उसकी भावनाओं को पूरी तरह समझती है, जबकि एआई के पास मानवीय अनुभव, नैतिक निर्णय, नैदानिक विवेक और वास्तविक सामाजिक संदर्भ को समझने की सीमाएं हैं। आत्महत्या या आत्महानि जैसे संकटपूर्ण मामलों में यह सीमा और अधिक गंभीर हो जाती है। व्यक्ति हमेशा सीधे शब्दों में अपनी स्थिति व्यक्त नहीं करता। उसके संकेत अप्रत्यक्ष, अस्पष्ट या सांस्कृतिक संदर्भों में छिपे हो सकते हैं। यदि एआई ऐसी चेतावनियों को पहचानने में विफल रहता है या समय पर मानवीय सहायता से नहीं जोड़ता, तो नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उच्च जोखिम वाले मामलों में चैटबॉट को बातचीत जारी रखने के बजाय प्रशिक्षित व्यक्ति, हेल्पलाइन या आपातकालीन सेवा की ओर तत्काल मार्गदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए। गोपनीयता भी एक बड़ी चिंता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातचीत अत्यंत निजी होती है। व्यक्ति अपनी भावनाएं, पारिवारिक परिस्थितियां, संबंध, भय और व्यक्तिगत अनुभव डिजिटल प्रणाली के साथ साझा कर सकता है। ऐसे संवेदनशील डेटा का संग्रह, भंडारण, उपयोग और साझा किया जाना स्पष्ट नियमों तथा मजबूत डेटा सुरक्षा के अधीन होना चाहिए। भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण संबंधी व्यवस्था के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य डेटा के लिए विशेष सावधानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, एआई में मौजूद एल्गोरिद्मिक पक्षपात भी चिंता का विषय है। भारत की भाषाई, सांस्कृतिक, लैंगिक और सामाजिक विविधता इतनी व्यापक है कि एक ही मॉडल सभी समुदायों की मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों को समान रूप से नहीं समझ सकता। किसी एक भाषा, वर्ग या सांस्कृतिक संदर्भ पर आधारित प्रशिक्षण से तैयार प्रणाली दूसरे समुदाय के लिए अनुपयुक्त सलाह दे सकती है। इसलिए आगे का रास्ता एआई को रोकना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ विकसित करना है।

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी एआई प्रणालियों के लिए स्वतंत्र नैदानिक परीक्षण, नियमित सुरक्षा ऑडिट, स्पष्ट जवाबदेही और संकट-स्थिति में मानव विशेषज्ञ तक पहुंचाने के अनिवार्य प्रोटोकॉल होने चाहिए। उच्च जोखिम वाले मामलों में मानव हस्तक्षेप को वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। साथ ही, डिजाइन के स्तर पर ही गोपनीयता, डेटा न्यूनतमकरण और सुरक्षित उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत में एआई मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहली चौखट को व्यापक बना सकता है। वह उस व्यक्ति तक पहुंच सकता है जो दूरी, खर्च, भाषा या सामाजिक कलंक के कारण चिकित्सक तक नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन पहली चौखट और अंतिम मंजिल में अंतर है। मानसिक स्वास्थ्य केवल सूचना या बातचीत का विषय नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, नैदानिक समझ और निरंतर देखभाल का क्षेत्र है। इसलिए भविष्य की सही दिशा 'एआई बनाम चिकित्सक' नहीं, बल्कि 'एआई के साथ चिकित्सक' होनी चाहिए। तकनीक पहुंच का विस्तार करे, प्रारंभिक संकेत पहचाने और सहायता की राह आसान बनाए; अंतिम निर्णय और देखभाल में प्रशिक्षित मानव विशेषज्ञ केंद्र में रहें। यही संतुलन भारत में सुरक्षित, सुलभ और मानवीय मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था की आधारशिला बन सकता है।

विचार

अन्तर विश्वविद्यालयी स्थानांतरण के पीछे भाजपा-आरएसएस की गहरी साज़िश

तीर्थंकर मित्रा

विधानसभा में भारी बहुमत होने के कारण उसके लिए काम करना आसान है, जबकि विपक्ष बंटा हुआ है। नतीजा यह है कि छात्रों के कल्याण को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। नई स्थानांतरण नीति निश्चित रूप से विचारों की विविधता पर बुरा असर डालेगी, जबकि यह देखना अभी बाकी है कि यह अकादमिक स्तर को कितना बेहतर बनाती है। श्चिम बंगाल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 राज्य विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में पास हो गया है। इसका मकसद शिक्षकों और गैर-शिक्षकों स्थानांतरण के लिए एक नई प्रणाली लाना है। इसका राज्य के विश्वविद्यालयों के माहौल पर गहरा असर पड़ेगा। पहली नज़र में, यह नई सरकार का उच्च शिक्षा को 'बेहतर' बनाने की दिशा में पहला कदम लग सकता है। सिद्धांत के तौर पर यह तारीफ़ के काबिल है। अनुभवी शिक्षक को नये विश्वविद्यालय में भेजने और उसके अकादमिक स्तर को बेहतर बनाने के इरादे पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी, ऐसा लगता है कि नज़रिए के हिसाब से यह अकादमिक तारीफ़ के काबिल नहीं है। शिक्षकों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने की ज़रूरतों के हिसाब से भर्ती किया जाता है। यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का हिस्सा है। असल में, उस स्वायत्तता को खत्म कर दिया गया है। यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में पेश किया गया। इसका समय जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के दो गुटों-एक वाम छात्र संघ और दूसरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद- के बीच रात में हुई अप्रिय झड़प के साथ मेल खाता है, जिसमें स्थानीय भाजपा विधायक सर्बोरी मुखर्जी ज़बरदस्ती अंदर घुस गईं। उन्होंने दूसरे गुट के छात्रों को गंभीर नतीजों की धमकी दी। इसके तुरंत बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक जुलूस ने जादवपुर विश्वविद्यालय के एक द्वार के पास रैली की। निष्पक्ष रुख का दिखावा छोड़कर, मुख्यमंत्री अधिकारी ने 'राष्ट्र-विरोधी नारे' लगाने वालों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार महात्मा गांधी की नहीं, बल्कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस की भाषा बोलेगी। वे यह भूल गए हैं कि बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज के टीचर ई.एफ. ओटेन के साथ टकराव के बाद एक छात्र नेता के तौर पर मशहूर हुए थे, जब ओटेन ने कथित तौर पर भारतीयों के ख़िलाफ़ कुछ नस्लवादी टिप्पणियां की थीं। अब, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कुछ छात्रों के ख़िलाफ़ एक छात्र नेता की भाषा बोलना चाहते हैं।

इसके अलावा, बोस सांप्रदायिक राजनीति से नफ़रत करते थे। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गठबंधन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जो उस समय बंगाल में हिंदू महासभा के एक बड़े नेता थे और जिन्होंने बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी- यही पार्टी आगे चलकर भाजपा बनी, जिससे अधिकारी जुड़े हैं। अब वर्तमान की बात करें तो, राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नया तरीका कुछ सवाल खड़े करता है। पहला सवाल यह है कि 'दूसरे विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित किए जाने वाले अनुभवी शिक्षकों की पहचान कौन करेगा? क्या राज्य सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने वाले शिक्षकों को सबसे पहले अपना बोरिया-बिस्तर समेटना होगा? क्या सत्ता में बैठे लोगों की राय के खिलाफ असहमति ही अकादमिक स्थानांतरण का मुख्य आधार होगी? किसी नए विश्वविद्यालय के अकादमिक स्तर को बेहतर बनाने का एकमात्र पैमाना हस्तांतरण नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि विश्वविद्यालय का अपना खास ध्यान किसी क्षेत्र पर हो और उसे अपने संसाधन और काबिलियत के क्षेत्रों को विकसित करने की आज़ादी हो। इन सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह के पक्षपात के शक को दूर करने के लिए इन पर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाना चाहिए था। जादवपुर विश्वविद्यालय के कई मौजूदा और पूर्व शिक्षकों ने परिसर में आकर छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई, जो भगवा विचारधारा को नहीं मानते थे। परिसर के अंदर बने राजनीतिक ग्रैफिटी को सफेदी से मिटा दिया गया, लेकिन उन पर फिर से कुछ लिख दिया गया। इसी माहौल में यह विधेयक पेश किया गया और पास हुआ। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि राज्य के शिक्षक समुदाय के एक बड़े हिस्से को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। इन अकादमिकों को डर है कि स्थानांतरण की यह नयी प्रणाली इस विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता के विकास के लिए खतरा है। इसकी प्रतिष्ठा रातों-रात नहीं बनी थी। आखिरकार, एक छोटे से बीज को बड़े पेड़ में बदलने में दशकों या उससे भी ज़्यादा समय लगता है। स्थानांतरण, खासकर किसी खास मकसद से किए गए स्थानांतरण, विश्वविद्यालय के प्रभाव को कम कर सकते हैं और उसके शिक्षण स्तर को अस्थिर कर सकते हैं - जैसे कि जादवपुर विश्वविद्यालय, जो हाल ही में गलत वजहों से चर्चा में रहा है।

एक नजर

छपरा के डबल डेकर पुल निर्माण कार्य दिन-रात तीन शिफ्टों में करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश

सारण,एजेंसी। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव तथा वरीय पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने आज शहर में निर्माणाधीन डबल डेकर पुल कार्य का स्थल निरीक्षण किया। अधिकारियों ने रामलीला मठिया और पुराने बस स्टैंड से लेकर भिखारी ठाकुर चौक तथा मोना चौक से मेवालाल चौक तक पूरे निर्माण क्षेत्र का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के परियोजना निदेशक को निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिकों और मशीनों की संख्या बढ़ाकर दिन-रात 24 घंटे तीन शिफ्टों में काम पूरा कराया जाए। सड़क, ड्रेनेज, गोलंबर और कंक्रीट से जुड़े सभी कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। जलजमाव से निपटने के लिए प्रभावित स्थानों पर तत्काल पंप लगाकर पानी निकालने और ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए गए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी को अभियंताओं की टीम के जरिए दैनिक निरीक्षण कर प्रतिदिन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। जलजमाव वाले क्षेत्रों में चूना व ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव तथा एयरपोर्ट परिसर से एक माह के भीतर मिट्टी हटाने की हिदायत दी गई। अतिक्रमण के मामले में भिखारी ठाकुर चौक स्थित नील कोठी की लगभग 50 दुकानों पर सदर अंचलाधिकारी को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया। निर्माण के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए सदर एसडीएम और ट्रैफिक डीएसपी को वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान तैयार कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश मिला। अंत में अधिकारियों ने पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण कर नगर आयुक्त को तत्काल जल निकासी सुनिश्चित करने और मुख्यमंत्री समग्र शहरी योजना के तहत छोटी प्राथमिक योजनाओं के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए, जिससे नालियों व सड़कों की जल्द मरम्मत हो सके।

माता रानी के दरबार में लगेगा सीवान का जयकारा, 18 सितंबर को रवाना होगा 200 श्रद्धालुओं का जत्था

सीवान,एजेंसी। श्रीमाता वैष्णो देवी दर्शन समिति, सीवान के तत्वावधान में माता रानी के दर्शन के लिए छह दिवसीय धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। समिति की ओर से आयोजित यह 13वीं वार्षिक यात्रा 18 सितंबर से शुरू होकर 23 सितंबर 2026 तक चलेगी। यात्रा में सीवान सहित आसपास के क्षेत्रों के करीब 200 श्रद्धालु शामिल होंगे। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि माता रानी के आशीर्वाद और कृपा से 18 सितंबर को श्रद्धालुओं का जत्था सीवान रेलवे स्टेशन से वैष्णो देवी धाम के लिए रवाना होगा। 19 सितंबर को श्रद्धालु पवित्र नगरी कटरा पहुंचेंगे। इसके बाद 20 सितंबर को श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन और पूजन करेंगे। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दर्शन के बाद 21 सितंबर को त्रिकूट पर्वत की तलहटी में स्थित हंसाली गांव में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यहां माता रानी के मंदिर के साथ माता सुलोचना और बाबा श्रीधर के मंदिर में कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन होगा। समिति की ओर से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए प्रसाद एवं भोजन की व्यवस्था की जाएगी। धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। यात्रा के निर्धारित कार्यक्रमों के बाद 23 सितंबर को श्रद्धालुओं की सीवान वापसी होगी। समिति के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह, सचिव अनूप कुमार तथा संरक्षक अरविंद कुमार पांडेय और विकास कुमार सिंह ने बताया कि समिति की ओर से वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष वैष्णो देवी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2026 में यह समिति की दूसरी यात्रा है। इससे पहले 3 अप्रैल को भी श्रद्धालुओं का जत्था वैष्णो देवी के लिए रवाना हुआ था। उस यात्रा के दौरान 6 अप्रैल को माता रानी के भूमिका मंदिर में भंडारा और कन्या पूजन का आयोजन किया गया था। पदाधिकारियों ने बताया कि समिति आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं को निशुल्क यात्रा कराने की पहल भी करती है। यात्रा प्रभारी सुधीर कुमार, बबलू सिंह, जितेंद्र कुमार तथा महिला यात्रा प्रभारी दुर्गा देवी सहित अन्य सदस्य यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। समिति का कहना है कि यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शन के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना है।

जमीन विवाद में अधेड़ पर लोहे की रॉड से हमला, भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

भागलपुर। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमर गामा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक 55 वर्षीय व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस हिंसक झड़प में बुरी तरह घायल हुए श्रीकांत सिंह की बुधवार को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।बताया जा रहा है कि कमर गामा गांव के रहने वाले श्रीकांत सिंह का कुछ लोगों के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिजन ने आरोप लगाया है कि इसी विवाद को लेकर घात लगाए हमलावरों ने श्रीकांत सिंह को घेर लिया और उन पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावरों की बेरहमी के कारण श्रीकांत सिंह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बचाने का हरसंभव प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतक के परिजन ने गांव के ही छह लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना की सूचना मिलते ही तारापुर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि जमीन विवाद के इस खूनी खेल में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट और केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने की बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा

पटना,एजेंसी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री-सह-ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में बाढ़ आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक देर शाम संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में बिहार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार ने बाढ़ राहत के क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा बाढ़ के दौरान तत्परतापूर्वक एवं बेहतर तरीके से किए गए राहत कार्यों की सराहना की तथा इसके लिए धन्यवाद दिया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ से आधारभूत संरचनाओं एवं फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। केला, मक्का, धान सहित अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है। केला, मक्का, लीची आदि फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा, जिससे बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों की पैदावार हो सके, किसानों की आय बढ़े तथा कृषि उत्पादों को विदेशों तक पहुंचाने की संभावनाओं को बल मिले। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वर्तमान परिस्थितियों में बिहार को अधिकतम सहयोग कैसे उपलब्ध कराया जा सके, इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा बाढ़ से हुए नुकसान एवं बिहार की आवश्यकताओं को प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा। उन्होंने बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने, जीविका दीदियों को सहायता उपलब्ध कराने तथा किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को बाढ़ राहत में अधिकतम सहयोग उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण प्रत्येक वर्ष बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित रहता है। इस वर्ष बाढ़ से लगभग 15 जिले के 88 प्रखण्ड के 50 लाख लोग प्रभावित हुये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों की मदद के लिये लगातार खड़ी रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों को एक हजार से अधिक सामुदायिक रसोई केन्द्रों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 62 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत शिविर में लोगों को सभी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में सभी संबद्ध विभागों ने केन्द्रीय मंत्री एवं उनकी टीम के सामने राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी दी है। बाढ़ से क्षति को लेकर आकलन कराया जा रहा है। बाढ़ से बिहार हर साल प्रभावित रहता है, इसके स्थायी समाधान के लिये काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम दृष्टया केंद्रीय मंत्री एवं उनकी टीम ने जो स्थिति को देखा है, उससे प्रधानमंत्री को भी अवगत करायेंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का पूरा आकलन दुर्गा पूजा से पहले कर लिया जाएगा तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।

शिक्षित बिहार से होकर ही गुजरेगा विकसित और समृद्ध बिहार का रास्ताः नीतीश कुमार

पटना,एजेंसी। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने बुधवार को नालंदा स्थित महाबोधि महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन एवं चारवर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम (आई.टी.ई.पी.) का उद्घाटन किया। नीतीश कुमार ने इस दौरान महाबोधि महाविद्यालय की शिक्षा एवं शोध को समर्पित वार्षिक पत्रिका 'नव चेतना' का विमोचन भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाबोधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अरविंद कुमार ने की।

मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियां ही किसी समाज, राज्य या देश के विकास का वास्तविक पैमाना होती हैं। उन्होंने कहा कि विकसित और समृद्ध बिहार का रास्ता शिक्षित बिहार से होकर ही गुजरेगा। इसके बिना न्याय के साथ विकास की सोच को भी पूरी तरह धरातल पर नहीं उतारा जा सकता। यही कारण है कि पिछले दो दशकों में एनडीए सरकार के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिए रहा है। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में महाबोधि महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन को महाविद्यालय के विकास की दिशा

में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि यहाँ का आधुनिक एवं सुविधायुक्त शैक्षणिक वातावरण विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व विकास को नई दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका की सराहना करते हुए कहा कि यह अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ साधने का अच्छा प्रयास है। समारोह में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं शिक्षा जगत से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें शिक्षा विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के समन्वयक डॉ कमल नयन प्रसाद, दीपक शर्मा, प्रो सुधीर कुमार वर्मा, डॉ कौशलेन्द्र कुमार, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार, विधान परिषद् में सत्तारूढ़ दल के उप-नेता ललन सर्राफ भी उपस्थित रहे।

सेवा स्मरण, सेवा ज्योति यात्रा से 25 साल, 25 कहानियाँ तक, बिहार में लोक संस्कृति बनेगी सेवा संकल्प अभियान की आवाज : डॉ. प्रमोद कुमार

पटना,एजेंसी। विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा एवं समर्पण से जुड़े सेवा संकल्प अभियान के तहत कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से सेवा स्मरण, सेवा ज्योति यात्रा और 25 साल, 25 कहानियाँ-नेशनल अनबॉक्सिंग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।

अभियान की तैयारियों को लेकर कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारियों को संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी कार्यक्रमों की समयबद्ध एवं प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। माननीय मंत्री ने कहा कि बिहार की समृद्ध लोक कला, लोक संगीत एवं लोक नाट्य परंपरा को अभियान से जोड़कर सेवा, समर्पण एवं 'विकसित भारत-2047' के संकल्प का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने स्थानीय कलाकारों, सांस्कृतिक दलों, युवाओं, विद्यार्थियों एवं आमजन की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। 'सेवा स्मरण' के तहत 17 सितंबर से विभिन्न जिलों में संगीतमय प्रस्तुतियों एवं नुक्कड़ नाटकों का आयोजन विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर किया जाएगा। 2 अक्टूबर को पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में विशेष मंचन आयोजित होगा। प्रत्येक जिले में लगभग 18-20 नाट्य एवं नुक्कड़ नाट्य टोलियों को अभियान से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। विद्यालयों में होने वाली अभिभावक शिक्षक मुलाकात के दौरान भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को अभियान से जोड़ा जाएगा। जिला, प्रखंड एवं ग्राम स्तर पर जनभागीदारी आधारित 'सेवा ज्योति यात्रा' आयोजित की जाएगी। इसमें युवाओं एवं सांस्कृतिक दलों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। यात्रा के समापन स्थल पर जनकल्याणकारी योजनाओं, लाभार्थी संवाद तथा 'विकसित भारत-2047' के संकल्प से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। '25 साल, 25 कहानियाँ-नेशनल अनबॉक्सिंग' के तहत भारत की विकास यात्रा से जुड़ी 25 प्रमुख योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली क्यूरेटेड किट तैयार की जाएगी।

पीएम मोदी के जन्मदिन पर बक्सर के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने लॉन्च की विकास यात्रा पर किताब

पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव निवासी प्रसिद्ध लेखक और वरिष्ठ पत्रकार मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने एक ऐसी पुस्तक को पाठकों के सामने रखा है, जो मौजूदा दौर की विकास यात्रा, नीतिगत बदलावों और भविष्य के भारत की परिकल्पना को दस्तावेजी रूप में सामने लाने का प्रयास करती है। पुस्तक का नाम है- 'मोदी युग का भारत'। पुस्तक में विकास की उस तस्वीर को सामने लाने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक ओर 'मेक इन इंडिया' के जरिए देश को विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश दिखाई देती है, तो दूसरी ओर डिजिटल क्रांति की पहुंच देश के सुदूर गांवों तक होती नजर आती है। महिला सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचे का विस्तार, बदलती अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका जैसे विषयों को भी पुस्तक में प्रमुखता दी गई है। 'मोदी युग का भारत' की खासियत यह बताई गई है कि इसमें सरकारी योजनाओं की सूची प्रस्तुत करने के बजाय उनके प्रभाव और व्यापक संदर्भ को समझने का प्रयास किया गया है। लेखक मुरली ने यह देखने की कोशिश की है कि नीतियों और योजनाओं का असर देश के आम नागरिक, गांव, युवा, महिलाएं और आर्थिक गतिविधियों पर किस तरह पड़ा।

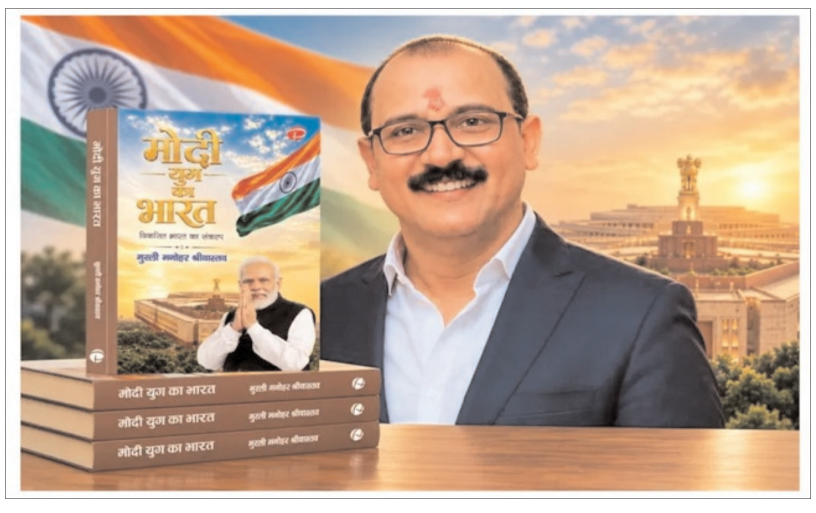

'मेक इन इंडिया' को पुस्तक में केवल एक नारे या औद्योगिक नीति के रूप में नहीं बल्कि भारत की उत्पादन क्षमता, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़कर देखने का प्रयास किया गया है। इसी तरह डिजिटल क्रांति को भी महज तकनीकी परिवर्तन नहीं माना गया है। लेखक के अनुसार, डिजिटल तकनीक ने सरकारी सेवाओं, बैंकिंग, भुगतान और सूचना तक आम लोगों की पहुंच को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पक्ष महिला सशक्तीकरण भी है। इसमें जमीनी स्तर पर महिलाओं की बदलती भूमिका और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाली पहलों को रेखांकित किया गया है। लेखक का प्रयास यह दिखाना है कि विकास की कहानी तभी पूरी मानी जा सकती है, जब समाज के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो। 'मोदी युग का भारत' का सबसे दिलचस्प और भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हिस्सा वह है, जहां लेखक 2047 के भारत की तस्वीर सामने रखने का प्रयास करते हैं। भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 में देश कैसा होगा-यह सवाल आज की युवा पीढ़ी के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही नीति-निर्माताओं के लिए भी। पुस्तक में इसी भविष्य को वर्तमान नीतियों और फैसलों के संदर्भ में समझाने का प्रयास किया गया है। लेखक का मानना है कि आज लिए जा रहे नीतिगत फैसले आने वाले दशकों के भारत की दिशा तय करेंगे। इसी सोच के आधार पर पुस्तक पाठकों को यह समझने का अवसर देती है कि बुनियादी ढांचे, तकनीक, विनिर्माण, महिला भागीदारी, आर्थिक विकास, वैश्विक कूटनीति और आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयास किस प्रकार भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जा सकते हैं।

बाढ़ प्रभावित किसानों के साथ खड़ी है सरकार, क्षति का वास्तविक आकलन कर मिलेगी हरसंभव सहायता : विजय कुमार सिन्हा

पटना,एजेंसी। बिहार में बाढ़ से प्रभावित किसानों को हुई फसल एवं कृषि संबंधी क्षति को लेकर राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बाढ़ का पानी कम होने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की वास्तविक क्षति का विस्तृत आकलन कराया जा रहा है। क्षति का आकलन शीघ्र पूरा कर किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। कृषि विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर फसल क्षति के आकलन एवं किसानों को फसल क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर सहायता मिल सके। मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया। दिघवारा एवं मनेर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण तथा वैशाली के तेरसिया एवं सरायपुर गांव में स्थलीय निरीक्षण के दौरान फसलों को हुए नुकसान का प्रत्यक्ष जायजा लिया और प्रभावित ग्रामीणों एवं किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि

केंद्रीय कृषि मंत्री का बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे जमीनी स्तर पर फसल एवं कृषि क्षेत्र को हुई क्षति की वास्तविक स्थिति को समझने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के साथ प्रभावित किसानों के लिए आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर आपदा की इस घड़ी में किसानों एवं उनके परिवारों की हरसंभव सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति के आकलन, राहत कार्यों तथा किसानों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि बाढ़ से प्रभावित कोई भी किसान सहायता से वंचित न रहे। फसल क्षति का वास्तविक आकलन होने के बाद निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

लालमुनी चौबे का जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित : अवधेश नारायण सिंह

पटना। स्वर्गीय लाल मुनी चौबे व्यक्ति नहीं विचार थे, बेमिसाल सादगी, ईमानदारी और विवाह के प्रतिमूर्ति लाल मुनी चौबे का पूरा जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित रहा है। आज के दौर में उन जैसा होना इतना आसान नहीं है। यह बातें बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कही। वे बिहार विधान परिषद के सभागार में लाल मुनी चौबे स्मृति न्यास कुरुथियाँ बक्सर के तत्वावधान में बुधवार को लाल मुनी चौबे की 84 जयंती पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे।

सभापतिअवधेश नारायण सिंह ने कहा कि लाल मुनी चौबे बक्सर से लगातार चार बार सांसद रहे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संस्थापक सदस्यों में से एक लाल मुनी चौबे का सानिध्य मुझे मिला। मैं सौभाग्यशाली हूं जो मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला और मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ उनसे सीखा है जिसे मैंने अमल भी किया। उक्त अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि लालमुनी चौबे बाबा जैसे लोग बिरल ही पैदा होते हैं। चौबे बाबा की ईमानदारी के सब कायल थे। वह दलगत घेरे से बाहर के राजनेता थे । हर पार्टी में उनको चाहने वाले हुआ करते थे। उनके व्यक्तित्व की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह क है। वो मरकर भी हम लोग के बीच प्रकाश पुंज की तरह अजय अमर है। उनके द्वारा किये गए उल्लेखनीय कार्य से आज के राजनेताओं को सीख लेने की जरूरत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार विधान परिषद के उप-सभापति डॉ. राम बचन राय, राजद के वरीय नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. अब्दुल बारी सिद्दीकी, विधान पार्षद जीवन कुमार, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक, चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह-संयोजक डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी ने भी लालमुनी चौबे के प्रति उदगार व्यक्त किया। मौके पर मुख्य रूप से लालमुनी चौबे के बड़े सुपुत्र हेमंत चौबे, भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री पूनम रविदास, राजवंश सिंह, भोला सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों भी उपस्थित रहें।

एक नजर

लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम में वापसी, 6 अक्टूबर को होगा विदाई मुकाबला

नई दिल्ली,एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी को अक्टूबर में होने वाले मैत्री मुकाबलों के लिए अर्जेंटीना की टीम में शामिल किया गया है। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ के अध्यक्ष क्लाउडियो तापिया ने पुष्टि की है कि मेसी को राष्ट्रीय टीम के लिए विदाई मुकाबला खेलने का निमंत्रण दिया गया है। तापिया ने सोशल मीडिया पर कहा, 'हमने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, अपनी टीम के आइकन और कप्तान लियोनेल मेसी को छह अक्टूबर को अर्जेंटीना में अपनी टीम के लिए एक योग्य विदाई के लिए खेलने का निमंत्रण दिया है। अर्जेंटीना अक्टूबर के अंतरराष्ट्रीय विंडो के दौरान तीन घरेलू मैत्री मुकाबले खेलेगा। मेसी के छह अक्टूबर को ब्यूनस आयर्स में बेनिन के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलने की उम्मीद है। इससे पहले अर्जेंटीना 30 सितंबर को कॉर्डोबा में बोलीविया और तीन अक्टूबर को ब्यूनस आयर्स में बुर्किना फासो का सामना करेगा। मेसी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी। ऐसे में छह अक्टूबर का मुकाबला उनके लिए राष्ट्रीय टीम की जर्सी में विदाई का अवसर बन सकता है। अर्जेंटीना की टीम में लिएंड्रो पेरेदेस, नाहुएल मोलिना और थियागो अल्माडा शामिल नहीं होंगे। विश्व कप फाइनल के बाद स्पेन के खिलाड़ियों के साथ हुए विवाद के चलते तीनों पर लंबा प्रतिबंध लगा हुआ है।

आईसीसी रैंकिंग: टी-20 में वरुण पांचवें, बुमराह शीर्ष-10 में पहुंचे; ओली रॉबिन्सन टेस्ट में तीसरे स्थान पर

दुबई। अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टी-20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन का फायदा भारतीय खिलाड़ियों को ताजा आईसीसी रैंकिंग में मिला है। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती दो स्थान की छलांग लगाकर पांचवें पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सात स्थान ऊपर चढ़कर शीर्ष-10 में शामिल हो गए हैं। विश्वकप चैंपियन भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में दिल्ली में खेले गए दूसरे मुकाबले के बाद 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। सीरीज के पहले दो मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने गेंद और बल्ले, दोनों से प्रभावी प्रदर्शन किया है। टी-20 गेंदबाजों की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती दो स्थान ऊपर पांचवें, जसप्रीत बुमराह सात स्थान ऊपर 10वें, अर्शदीप सिंह 11 स्थान की छलांग लगाकर 14वें और अक्षर पटेल छह स्थान ऊपर 27वें पायदान पर पहुंच गए हैं। टी-20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा को भी शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला है। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 82 रन की तूफानी पारी खेलने वाले अभिषेक एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़ा है। अभिषेक से आगे अब केवल ईशान किशन हैं। दोनों भारतीय बल्लेबाजों के बीच 51 रेटिंग अंकों का अंतर है। वहीं, दूसरे मैच में अर्धशतक लगाने वाले संजू सैमसन चार स्थान ऊपर चढ़कर 30वें पायदान पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान के लिए भी ऑलराउंडरों की रैंकिंग में अजमतुल्लाह उमरजई ने प्रगति की है। 26 वर्षीय उमरजई ने सीरीज के पहले मैच में नाबाद अर्धशतक लगाया था।

वनडे रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को फायदा

वनडे रैंकिंग में जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में 59 रन से मिली जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। तेज गेंदबाज नाथन एलिस पांच विकेट लेने के बाद 20 स्थान ऊपर चढ़कर गेंदबाजों की सूची में 20वें पायदान पर पहुंच गए हैं। मैच में 109 रन की शानदार पारी खेलने वाले मैथ्यू रेनशॉ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। उन्हें भी रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है और वह शीर्ष-100 से बाहर की स्थिति से सीधे 68वें पायदान पर पहुंच गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 51 रन बनाने वाले कूपर कोनोली नौ स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

टेस्ट रैंकिंग में ओली रॉबिन्सन का करियर बेस्ट

टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है। पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 21 विकेट लेने के बाद रॉबिन्सन दो स्थान ऊपर चढ़कर टेस्ट गेंदबाजों की सूची में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के ही जोश टंग ने भी दो स्थान की बढ़त के साथ 11वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 19 विकेट लिए थे, जो उनकी नई करियर-बेस्ट रैंकिंग है। बर्मिंघम में खेले गए तीसरे टेस्ट में ओली रॉबिन्सन ने अर्धशतक भी लगाया था। इसके बाद वह टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में सात स्थान ऊपर चढ़कर 13वें पायदान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के लिए टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम दो स्थान ऊपर चढ़कर 13वें और शान मसूद चार स्थान ऊपर चढ़कर 37वें पायदान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ भी तीन स्थान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने तीसरे टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक लगाया था।

एशियाई खेल: भारतीय महिला हॉकी टीम को कोच मारिजने का संदेश- स्वर्ण पदक के लिए फिर लड़ना होगा

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई खेल 2026 में 44 साल के स्वर्ण पदक के इंतजार को खत्म करने और लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालीफाई करने के इरादे से जापान पहुंच चुकी है। विश्वकप 2026 में ऐतिहासिक पांचवां स्थान हासिल करने के बाद टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है लेकिन मुख्य कोच सजोर्ड मारिजने ने खिलाड़ियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि विश्वकप की सफलता अब पीछे छूट चुकी है और एशियाई खेलों में स्वर्ण के लिए उन्हें फिर से पूरी ताकत लगानी होगी। भारतीय महिला टीम ने 1982 के बाद एशियाई खेलों में सिर्फ एक बार स्वर्ण पदक जीता है। ऐसे में जापान में होने वाले मुकाबले टीम के लिए इतिहास बनाने का अवसर हैं। विश्वकप में पांचवें स्थान के रूप में भारत ने 52 वर्षों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। मारिजने ने कहा कि विश्वकप के बाद बेंगलुरु में खिलाड़ियों को सक्रिय आराम दिया गया और जापान पहुंचने के बाद टीम समय के अंतर के साथ तालमेल बैठाने और प्रशिक्षण में तेजी लाने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, 'हम बहुत खूबसूरत माहौल में हैं और अब हर कोई एशियाई खेलों पर पूरी तरह केंद्रित है।'

शारीरिक तैयारी के बारे में मारिजने ने बताया कि डॉ. वेन लोम्बार्ड और उनकी टीम खिलाड़ियों के लिए शारीरिक कार्यक्रम तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण करना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आराम, उसकी सही प्रक्रिया और स्ट्रेंथ सेशन भी उतने ही जरूरी हैं। उन्होंने कहा, 'वेन खिलाड़ियों की निगरानी करते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी नींद कैसी है और क्या वे तरोताजा हैं। स्टाफ के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षण की तीव्रता कितनी रखी जा सकती है। वे मुझे बताते हैं कि मेरे सत्र में ऊर्जा और तीव्रता का स्तर कितना हो सकता है।'

विश्वकप की उपलब्धि को पीछे छोड़ने के बारे में मारिजने ने कहा कि उन्होंने जापान रवाना होने से पहले बेंगलुरु में खिलाड़ियों के लिए विशेष जापानी भोजन की व्यवस्था कराई और उस दौरान टीम से विश्वकप के अनुभव को एक बार फिर याद करने के बाद अगले अध्याय पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा, 'हमने कुछ शानदार और ऐतिहासिक किया है लेकिन अब हमें अगले टूर्नामेंट की ओर बढ़ना होगा। मैंने खिलाड़ियों से कहा कि जीवन में बाद में वे विश्वकप को याद करेंगी कि हमने कितना शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन आपको एक अध्याय बंद करके अगले अध्याय की ओर बढ़ना होता है।' उन्होंने बताया कि वीडियो विश्लेषक ने विश्वकप के गोल और यादगार पलों को शामिल करते हुए एक फिल्म तैयार की, जिसकी अंतिम स्लाइड पर 'एशियाई खेलों की राह' लिखा था। मारिजने ने खिलाड़ियों को यह भी याद दिलाया कि सफलता अपने आप नहीं मिलती। उन्होंने कहा, 'सफलता की गारंटी नहीं है। आपको इसके लिए फिर से लड़ना होगा और पहले से भी ज्यादा देना होगा।'

विश्वकप में पदार्पण करने वाली 11 खिलाड़ियों के अनुभव पर मारिजने ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेल संस्कृतियों और शैलियों का सामना किया है, जिसका इस्तेमाल टीम भविष्य की तैयारी में कर सकती है। उन्होंने कहा, 'हम विश्वकप के बाद टीम के तौर पर सुधार करने पर ध्यान दे रहे हैं। मैं और ज्यादा चाहता हूं क्योंकि अगर हम यह सोचकर रुक जाते हैं कि हम वहां पहुंच चुके हैं तो यही वह पहला चरण होता है जब सुधार रुक जाता है।'

एशियाई खेलों में सविता के भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाने के सवाल पर मारिजने ने कहा कि टीम व्यक्तिगत उपलब्धियों से ज्यादा सामूहिक लक्ष्य पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, 'सविता बहुत पेशेवर हैं इसलिए मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी टीम पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है तो वह सविता हैं। मुझे लगता है कि बाकी खिलाड़ी भी उनके लिए और ज्यादा मेहनत करना चाहती हैं। हम एक टीम के रूप में बहुत केंद्रित हैं, व्यक्तिगत उपलब्धियों पर नहीं। हम जश्न भी टीम के रूप में मनाते हैं।'

विश्वकप में भारतीय टीम की मजबूत रक्षापंक्ति और जर्मनी पर 3-1 की जीत से मिले आत्मविश्वास पर मारिजने ने कहा कि इन मुकाबलों ने टीम को भरोसा दिया है कि उसकी तैयारी और खेलने का तरीका काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि लगातार मेहनत के बिना वही चीजें आगे भी काम करेंगी, इसकी गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा, 'बुनियादी चीजें अच्छी होनी चाहिए। दौड़ना, तीव्रता और ये सभी छोटी-छोटी चीजें महत्वपूर्ण हैं। एशियाई खेलों में चीन से मिलने वाली चुनौती के बारे में मारिजने ने कहा कि टीम रणनीति बनाते समय किसी विशेष देश पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उन्होंने कहा, 'मैं टीम से बात करते समय चीन, जापान या कोरिया जैसे देशों के नाम का इस्तेमाल बहुत कम करता हूं। हम खुद पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। दूसरे देश क्या कर रहे हैं, इसमें मेरी रुचि नहीं है। हमें अपना खेल बहुत अच्छी तरह करना है और फिर नतीजा अच्छा हो सकता है। भारत में उन्हें 'चक दे' कोच कहे जाने पर मारिजने ने कहा कि उनके लिए खिलाड़ियों, अपने स्टाफ, हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मजबूत संबंध सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, 'मैं भारत में खुद को बहुत सम्मानित और सराहा हुआ महसूस करता हूं। हर व्यक्ति को यह अच्छा लगता है। 'चक दे इंडिया' से जुड़ी कहानियां सुनना भी शानदार है। लड़कियां भी कभी-कभी इसके बारे में बात करती हैं इसलिए यह काफी मजेदार लगता है।'

जेम्स रोड्रिगेज ने कोलंबिया की राष्ट्रीय टीम से संन्यास लिया

बोगोटा। कोलंबिया के स्टार मिडफील्डर जेम्स रोड्रिगेज ने मंगलवार को 15 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा कर दी। 35 वर्षीय रोड्रिगेज ने उत्तरी अमेरिका में हुए हालिया फीफा विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहने का फैसला किया।

रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'कई वर्षों, मैचों, खुशी के पलों और मुश्किल दौर से गुजरने के बाद मुझे लगता है कि अब अपनी जिंदगी के एक अध्याय को बंद करने का समय आ गया है—कोलंबिया की राष्ट्रीय टीम के साथ मेरा सफर। इस जर्सी को पहनना एक सपना था, लेकिन यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी।' रोड्रिगेज ने 2011 में ला पाज में बोलीविया के खिलाफ जीत के दौरान कोलंबिया के लिए पदार्पण किया था। हालांकि 2014 फीफा विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने टूर्नामेंट में गोल्डन बूट जीता और इसके बाद स्पेन के दिग्गज क्लब रियल मैड्रिड से जुड़ गए। रियल मैड्रिड के साथ उन्होंने दो ला लीगा खिताब जीते। इसके अलावा वह बायर्न म्यूनिख और एवर्टन के लिए भी खेल चुके हैं। उन्होंने कहा, 'मैं उन पलों को जीने के लिए भाग्यशाली रहा, जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी—विश्व कप, गोल और अविस्मरणीय रातें; ऐसी जीत जिन्होंने हमें विश्वास करना सिखाया और ऐसी हार जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। रोड्रिगेज ने कहा, 'जब मैंने राष्ट्रीय टीम के साथ सफर शुरू किया था, तब मेरी इच्छा थी कि जब मैं आगे बढ़ूं तो टीम की जर्सी को पहले से अधिक मजबूत स्थिति में छोड़कर जाऊं। पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने यह हासिल किया। उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नंबर 10 की जर्सी और कप्तान का आर्मबैंड पहनने का सम्मान मिला। मैंने इसे सम्मान, जिम्मेदारी और इस बात की समझ के साथ निभाने की कोशिश की कि कोलंबिया का प्रतिनिधित्व करने का क्या मतलब है। मेरे अच्छे दिन भी रहे और मुश्किल दिन भी, लेकिन मुझे इन रंगों पर गर्व महसूस होना कभी बंद नहीं हुआ।'

एशियाई खेल: मां से किया वादा निभाकर असीमा ने बनाया भारतीय टीम में स्थान

नई दिल्ली,एजेंसी। असीमा अहलावत के लिए शूटिंग का सफर पढ़ाई से शुरू होकर एशियाई खेलों तक पहुंचा है। 18 साल की उम्र में पिस्टल से निशानेबाजी शुरू करने वाली 22 वर्षीय असीमा ने बाद में शॉटगन को अपना खेल चुना। यह बदलाव उन्होंने अपनी मां से किए एक वादे के बाद किया था। मां ने उन्हें शूटिंग में करियर बनाने की अनुमति देने से पहले पढ़ाई में अच्छे अंक लाने की शर्त रखी थी। असीमा ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 98.6 प्रतिशत अंक हासिल कर अपना वादा पूरा किया। अब चार साल बाद रोहतक, हरियाणा की असीमा आइची-नागोया एशियाई खेलों में पदार्पण करने के लिए तैयार हैं। असीमा के खेल से जुड़ने की कहानी भी दिलचस्प है। निर्माण कारोबार से जुड़े परिवार में पली-बढ़ी असीमा ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के बाद निशानेबाजी की ओर आकर्षित होना शुरू किया। उन्होंने एक बयान में कहा, 'मंच पर मनु भाकर और हीना सिद्धू को देखकर मुझे याद है कि मैंने सोचा था, मैं भी किसी दिन ऐसा महसूस करना चाहती हूं। असीमा के इस सफर में उनकी मां की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा, 'मेरी मां ने मुझे सिर्फ अनुमति नहीं दी, बल्कि इसके लिए बहुत कुछ छोड़ा भी। वह रोहतक से दिल्ली आ गईं, उन्होंने हमारे पारिवारिक कारोबार को भी स्थानांतरित किया, ताकि मैं ठीक से प्रशिक्षण ले सकूं। मैं इस बात को हल्के में नहीं लेती।

शूटिंग के शुरुआती वर्षों में भी असीमा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी पहली शॉटगन और गोला-बारूद की व्यवस्था होने में करीब आठ महीने लग गए। उन्होंने कहा, 'पदक ही यह बताने का एकमात्र तरीका नहीं है कि आपने कितनी दूर तक सफर तय किया है। उन्होंने आगे कहा, 'अगर कुछ सही नहीं होता है तो मैं गलती तलाशती हूं, उसे सुधारती हूं और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ वापसी करती हूं।' यही सोच 2024 में पेरू में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भी उनके काम आई। अपने जूनियर करियर के अंतिम वर्ष में एक गलत गणना के कारण वह अंतिम निशाने से चूक गईं और चौथे स्थान पर रहीं। इसके कुछ सप्ताह बाद उन्होंने दिल्ली में आयोजित विश्व विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। असीमा अपनी प्रगति का श्रेय राष्ट्रीय राइफल संघ को भी देती हैं। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय राइफल संघ ने मेरे जैसे निशानेबाजों के लिए चीजों को काफी आसान बनाया है। प्रशिक्षण शिविर, प्रतियोगिताएं और यहां तक कि गोला-बारूद की नियमित उपलब्धता जैसी बुनियादी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। खेल से बाहर के लोगों को इसका अंदाजा नहीं होता, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा, 'पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय राइफल संघ के शिविरों से मुझे जो अनुभव और अवसर मिले हैं, उनके बिना मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी तेजी से आगे बढ़ पाती। निशानेबाजी के मानसिक दबाव से निपटने के लिए असीमा ने अपना अलग तरीका विकसित किया है। खुद को जरूरत से ज्यादा सोचने वाली बताने वाली असीमा ने कहा, 'मैं अपनी सांसों पर ध्यान देती हूं और सच कहूं तो निशानेबाजी के दौरान अपने दिमाग में कोई भी गाना लगातार चलाती रहती हूं। यह मुझे उस पल में शांत और सुरक्षित महसूस करने का मेरा तरीका है, जो अन्यथा काफी अकेला होता है। आइची-नागोया एशियाई खेलों को लेकर असीमा का लक्ष्य भी स्पष्ट है। उन्होंने कहा, 'मेरा प्लान निशाना-दर-निशाना आगे बढ़ने का है। मैं पूरे समय पदक के बारे में नहीं सोचना चाहती। मैं सिर्फ वर्तमान में रहना और इस प्रक्रिया का आनंद लेना चाहती हूं। भविष्य को लेकर उन्होंने कहा, 'मेरा अगला बड़ा लक्ष्य फिर से टीम में जगह बनाना, ओलंपिक कोटा हासिल करना और ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। यही वह सपना है जिसका मैं अब पीछा कर रही हूं।'

एशियाई खेल: स्वर्ण पदक बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी भारतीय महिला कबड्डी टीम

नई दिल्ली,एजेंसी। एशियाई खेल-2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। कप्तान पुष्पा राणा और अर्जुन पुरस्कार विजेता पूजा काजला ने टीम की तैयारियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारतीय टीम का लक्ष्य शीर्ष स्थान हासिल करना है। भारतीय 12 सदस्यीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहीं पुष्पा राणा ने कहा कि टीम ने विरोधी टीमों का विश्लेषण करने के साथ अपनी कमजोरियों पर भी काम किया है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'हम परिस्थितियों के अनुसार अभ्यास करते हैं। आगामी मुकाबलों के वीडियो का भी विश्लेषण करते हैं। हमारे कोच हमें पिछली गलतियों और उन क्षेत्रों के बारे में बताते हैं, जिनमें सुधार की जरूरत है। अब हम उन्हीं पहलुओं पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी टीम पूरी तरह तैयार है।

एशियाई खेलों में कबड्डी में भारत का दबदबा रहा है और देश ने इस खेल में अब तक 11 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें महिला वर्ग के तीन स्वर्ण शामिल हैं। भारतीय महिला टीम ने हांगझोउ एशियाई खेलों में चीनी ताइपे को फाइनल में 26-25 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। पिछले साल नवंबर में भारतीय महिला टीम ने विश्व कप का खिताब भी अपने नाम किया था। राणा ने कहा कि लगातार खिताब जीतने की उम्मीद उनके लिए दबाव नहीं, बल्कि प्रेरणा है। उन्होंने कहा, 'जब हमारी सीनियर खिलाड़ियों ने पहले ही अच्छा प्रदर्शन किया है और अपना इतिहास बनाया है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस लय को बनाए रखें। हम इसे दबाव के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरणा के रूप में देखते हैं और इस लय को बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पुष्पा राणा पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रही हैं। हालांकि वह पहले उपकप्तान की भूमिका निभा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि टीम में मौजूद अनुभवी खिलाड़ियों से उन्हें काफी मदद मिल रही है। राणा ने कहा, 'मैं सीनियर खिलाड़ियों पर काफी भरोसा करती हूं, क्योंकि ऋतु नेगी और सोनाली शिंगाटे जैसी खिलाड़ी पहले कप्तानी कर चुकी हैं। इसलिए उनकी सलाह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राणा ने चीनी ताइपे को एशियाई खेलों में भारत के लिए प्रमुख चुनौती पेश करने वाली टीमों में शामिल बताया। उन्होंने पिछले एशियाई खेलों के बेहद करीबी फाइनल का भी जिक्र किया, जिसमें भारत ने चीनी ताइपे को 26-25 से हराया था। अर्जुन पुरस्कार विजेता पूजा काजला ने कहा कि एशियाई खेलों में एक और स्वर्ण पदक जीतना भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए अगली पीढ़ी को प्रेरित करने का अवसर भी होगा। उन्होंने कहा, 'सबसे पहले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जब हम महिला खिलाड़ियों की सफलता की बात करते हैं, तो छोटी उम्र की लड़कियां भी उनसे प्रेरित होती हैं। अगर हम स्वर्ण पदक जीतते हैं तो छोटे बच्चों को हमसे प्रेरणा मिलेगी और वे भी अपने माता-पिता से खेल खेलने के लिए कहेंगे। काजला ने अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया और प्रो कबड्डी लीग के आयोजक मशाल स्पोर्ट्स की ओर से आयोजित स्ट्रेंथ एवं कंडीशनिंग शिविर को भी उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि शिविर में खिलाड़ियों को नींद और रिकवरी से जुड़ी अतिरिक्त कक्षाएं दी गईं, जिससे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। एशियाई खेल 2026 की कबड्डी प्रतियोगिता 21 सितंबर से शुरू होगी। भारतीय महिला टीम ग्रुप-ए के अपने पहले मुकाबले में 21 सितंबर को बांग्लादेश का सामना करेगी। इसके बाद 23 सितंबर को ईरान और 24 सितंबर को जापान से मुकाबला होगा।

एशियाई खेल 2026: जापान पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम, कोच मजूमदार ने चुनौती को लेकर जताई उत्सुकता

टोक्यो। हाल ही में टी20 एशिया कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियाई खेल 2026 में अपने अभियान के लिए जापान पहुंच गई है। गत चैंपियन भारतीय टीम की नजरें हांगझोउ में 2023 में जीते स्वर्ण पदक का बचाव करने पर हैं। मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने कहा कि टीम बहु-खेल आयोजन के माहौल का अनुभव लेने के लिए उत्साहित है। जापान पहुंचने के बाद मजूमदार ने कहा, 'टीम एशियाई खेलों को लेकर उत्साहित है और बहु-खेल आयोजन के माहौल का आनंद लेने के लिए तैयार है।

मजूमदार अपने सहयोगी स्टाफ के कुछ सदस्यों के साथ सुबह की उड़ान से जापान पहुंचे। क्रांति गौड़ और श्री चरणी सहित टीम की कुछ खिलाड़ी कोचिंग स्टाफ के साथ जापान पहुंचीं, जबकि टीम की बाकी सदस्य दिन में बाद में पहुंचने वाली थीं। मजूमदार ने कहा कि अलग-अलग खेलों के खिलाड़ियों के साथ रहना, गेम्स विलेज में समय बिताना और बहु-खेल मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना खिलाड़ियों के लिए एक अलग अनुभव होगा। उन्होंने कहा, 'बहु-खेल आयोजन का माहौल ऐसी चीज है, जिसका टीम बेसब्री से इंतजार कर रही है। हम चाहते हैं कि खिलाड़ी इस अनुभव का भी आनंद लें।' उन्होंने यह भी बताया कि टीम को आवास को लेकर कोई परेशानी नहीं है। भारतीय टीम हाल के मुकाबलों में शानदार फॉर्म में रही है और इस दौरान श्री चरणी ने गेंदबाजी में अहम भूमिका निभाई है। 22 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर ने टी20 एशिया कप में 12 विकेट लेकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया। श्री चरणी ने लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल 30 मैचों में 50 विकेट का आंकड़ा भी पार कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत को उनकी फॉर्म से काफी उम्मीदें रहेंगी। भारत अपने अभियान की शुरुआत 18 सितंबर को मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले से करेगा। यह मैच निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में केवल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं और मुकाबले सीधे क्वार्टर फाइनल चरण से शुरू होंगे। ऐसे में भारतीय टीम के पास शुरुआत में लय हासिल करने के लिए ज्यादा अवसर नहीं होंगे। भारत ने हांगझोउ में 2023 एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता था और अब टीम अपने खिताब का बचाव करने के इरादे से मैदान में उतरेगी।

एक नजर

असद शासन की आतंकवाद निरोधक अदालत को सीरिया की संसद ने किया समाप्त

दमिश्क,एजेंसी। सीरिया की संसद ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन के दौरान बनाई गई आतंकवाद निरोधक अदालत को समाप्त करने और उसके फैसलों के कानूनी प्रभाव को खत्म करने के पक्ष में मतदान किया। सरकारी अल-इख्बारिया टीवी ने यह जानकारी दी। नई संसद के गठन के बाद इसे उसके शुरुआती महत्वपूर्ण विधायी फैसलों में से एक माना जा रहा है। 'काउंटर-टेररिज्म कोर्ट' की स्थापना वर्ष 2012 में असद सरकार के खिलाफ शुरू हुए विद्रोह के बीच की गई थी। इस अदालत में आतंकवाद से जुड़े आरोपों के तहत बड़ी संख्या में सीरियाई नागरिकों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए थे। संसद का ताजा फैसला उस प्रक्रिया को औपचारिक रूप देता है, जिसके तहत नई सीरियाई सरकार पहले ही इस अदालत को समाप्त मान चुकी थी। जून 2025 में राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने 67 न्यायाधीशों को पद से हटाने का आदेश दिया था। ये न्यायाधीश उस अदालत में कार्यरत थे, जिसे उन्होंने उस समय 'समाप्त आतंकवाद निरोधक अदालत' बताया था। मार्च 2025 में जारी सीरिया की संवैधानिक घोषणा में भी अदालत द्वारा दिए गए अन्यायपूर्ण फैसलों के प्रभाव को खत्म करने की बात कही गई थी। इसमें जब्त की गई संपत्तियों को उनके मालिकों को लौटाने का प्रावधान भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने 2024 में अदालत की स्थापना से जुड़े कानून पर चिंता जताई थी। समिति के अनुसार, कानून में निष्पक्ष न्याय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण गारंटियां पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं थीं। उसने मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने, यातना या दुर्व्यवहार तथा अदालत की स्वतंत्रता को लेकर भी सवाल उठाए थे।

ईसाइयों के उत्पीड़न के आरोप पर नेतन्याहू का पलटवार, कहा- इजराइल में समुदाय सुरक्षित

यरूशलम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में ईसाई समुदाय के उत्पीड़न के आरोपों को खारिज करते हुए इसे 'झूठ' बताया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ईसाइयों की रक्षा करता है और देश के ईसाई समुदाय के लोग भी इजराइल की सुरक्षा में योगदान देते हैं। अरबी भाषी ईसाई इजराइली सैनिकों की स्मृति में प्रस्तावित स्मारक के शिलान्यास समारोह में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल और उसकी सेना के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाया जा रहा है। उनके मुताबिक, इस अभियान में इजराइल पर युद्ध अपराधों और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। नेतन्याहू ने इजराइल को प्रगति, सहिष्णुता और सुरक्षा का केंद्र बताते हुए कहा कि देश अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सीरिया में द्रूज समुदाय की सुरक्षा के प्रति भी इजराइल की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि स्मारक का यह समारोह उन आरोपों को खारिज करने का प्रतीक है कि इजराइल ईसाइयों को निशाना बनाता है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि मध्य पूर्व में इजराइल ही ऐसा स्थान है, जहां ईसाई समुदाय लगातार बढ़ रहा है और फल-फूल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अन्य हिस्सों में ईसाइयों को कथित तौर पर उत्पीड़न, पलायन या हिंसा का सामना करना पड़ रहा है।

नेपाल में विदेशी पर्यटकों के लिए होगी 'पासपोर्ट-फ्री ट्रैवल' व्यवस्था, मोबाइल ऐप में दिखेगा डिजिटल पासपोर्ट

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के आव्रजन विभाग ने 'पासपोर्ट-फ्री ट्रैवल' की अवधारणा लागू करने की तैयारी की है। इसके तहत नेपाल घूमने आने वाले विदेशी पर्यटकों को यात्रा के दौरान अपने साथ पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं होगी। पर्यटक अपने मोबाइल में आव्रजन विभाग के ऐप के जरिए पासपोर्ट का डिजिटल विवरण दिखा सकेंगे। इसके लिए पर्यटकों को 'डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन' मोबाइल ऐप में लॉगिन कर अपने पासपोर्ट की जानकारी दर्ज करनी होगी। विभाग के निदेशक टीकाराम ढकाल के मुताबिक, ऐप पर प्रदर्शित पासपोर्ट विवरण को नेपाल के सभी संबंधित निकायों में मान्यता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से पर्यटकों को यात्रा में सुविधा होगी और सरकार के लिए डिजिटल ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी। शुरुआत में नेपाल प्रवेश के समय पर्यटक को आव्रजन कार्यालय में पासपोर्ट दिखाकर मोबाइल ऐप में लॉगिन करना होगा। इसके बाद नेपाल में यात्रा के दौरान पासपोर्ट साथ रखने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में हिमालय में पर्वतारोहण के दौरान भी पर्यटकों को अपना पासपोर्ट साथ रखना पड़ता है। विभाग का कहना है कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था तैयार की गई है। इस व्यवस्था से संबंधित सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर विभाग ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया है। प्रवक्ता ढकाल ने बताया कि मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

नेपाल के रसुवा में चिलिमे हाइड्रोपावर की सुरंग में मिले चार शव, छह कर्मचारी अभी भी लापता

काठमांडू। नेपाल के रसुवा स्थित चिलिमे हाइड्रोपावर परियोजना की सुरंग के अंदर चार शव बरामद किए गए हैं। खोज और बचाव अभियान में जुटी टीम ने बुधवार को सुरंग के भीतर से चार शव बरामद किए। चिलिमे जलविद्युत परियोजना के बचाव अभियान में तैनात सशस्त्र पुलिस निरीक्षक वकील बहादुर धानुक ने इसकी पुष्टि की है। रसुवा की भोटेकोसी नदी में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से चिलिमे समेत कई जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा था। बाढ़ में परियोजनाओं में कार्यरत कई मजदूर और कर्मचारी लापता हो गए थे। चिलिमे परियोजना के पावर हाउस और गेट पर कार्यरत छह कर्मचारी अभी भी लापता हैं। आशंका थी कि वे परियोजना के अंदर फंस गए होंगे। सुरंग के अंदर लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए नेपाली सेना और सशस्त्र पुलिस के 11 सदस्यों की टीम खोज एवं बचाव अभियान में जुटी थी।

बाढ़ के 21वें दिन भी तलाश जारी, 1,399 शव मिले; 5,179 लोग अब भी लापता

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल में गत 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के 21वें दिन भी खोज और राहत अभियान जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1,399 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 5,179 लोग अभी भी लापता हैं। करीब 21 हजार सुरक्षाकर्मी अब भी खोज, बचाव और राहत कार्यों में जुटे हैं। जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों, नदी के किनारों, आसपास के जंगलों और बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजाराम बस्नेत के अनुसार सेना के करीब 8,900 जवान सीधे खोज, बचाव और समन्वय कार्यों में तैनात हैं। सशस्त्र पुलिस के करीब 5,000 जवान भी अभियान में शामिल हैं। इनके द्वारा बचाव अभियान चलाने के साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाल पुलिस के करीब 8,000 जवान भी खोज और बचाव कार्य में लगाए गए हैं। बाढ़ में रसुवा और नुवाकोट स्थित नेपाल पुलिस के पांच कार्यालय भी बह गए थे, जिन्हें अभी तक पूरी तरह पुनर्स्थापित नहीं किया जा सका है। रसुवा के स्याफ्रुबेसी क्षेत्र में खोज और बचाव के लिए सेना की तीन टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ में स्याफ्रुबेसी बाजार का बड़ा हिस्सा बह गया था और वहां पहुंचने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत एवं खोज अभियान में देरी हुई। सेना प्रभावित कोलोनी, तुप्चे, दानसिंग, सामरी भंज्यांग, कालिकास्थान और मानचेत समेत कई इलाकों में पैदल गश्त भी कर रही है। दुर्गम और सड़क संपर्क से कटे इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। नेपाली सेना के

ड्रोन से नुवाकोट में 16,138 किलोग्राम और रसुवा में 5,861 किलोग्राम राहत एवं आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा चुकी है।

चीन सीमा से लगे प्रमुख व्यापारिक बाजार टिमुरे में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। सशस्त्र पुलिस की बीओपी को छोड़कर लगभग सभी सरकारी कार्यालय बह गए हैं। तीन सप्ताह बीतने के बाद भी सशस्त्र पुलिस के अलावा अन्य सरकारी एजेंसियां वहां पूरी तरह नहीं पहुंच सकी हैं। टिमुरे बाजार से 100 से अधिक शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन बाढ़ से ध्वस्त मकानों में अब तक खुदाई शुरू नहीं हो पाई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेपाल पुलिस की मौजूदगी नहीं होने के कारण भी खुदाई और बरामदगी की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। टिमुरे का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। टिमुरे से करीब दो किलोमीटर ऊपर स्थित रसुवागढी नाके तक जाने वाली सड़क भी नहीं है, जबकि टिमुरे से करीब 16 किलोमीटर नीचे स्याफ्रुबेसी तक का मार्ग पूरी तरह बह गया है। चिलिमे और लांगटांग जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों के साथ संयुक्त बचाव दल खोज अभियान चला रहा है। चिलिमे परियोजना की सुरंग में पानी निकलने वाली जगह पर छेद बनाकर बचाव दल करीब 130 मीटर अंदर तक पहुंच चुका है। मलबा हटाने के लिए एक्स्कावेटर और लोडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपर त्रिशूली-1 के 'ऑडिट-3' में नेपाली सेना और परियोजना के प्रतिनिधियों सहित बचाव दल करीब 600 मीटर अंदर तक पहुंच चुका है। वहीं त्रिशूली-3ए की सुरंग और पावर हाउस क्षेत्र में भी संयुक्त टीम खोज अभियान चला रही है।

गाजा के 20 से अधिक अस्पतालों को डीजल सप्लाई बंद कर सकता है डब्ल्यूएचओ

तेहरान। गाज़ा में स्वास्थ्य सेवाओं पर एक और संकट मंडराने लगा है। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टर-जनरल डॉ. मुनीर अल-बुर्श के मुताबिक, फंड की कमी के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) 19 सितंबर से गाज़ा के 20 से अधिक अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स को डीज़ल की सप्लाई बंद कर सकता है। ईरान की अर्ध-आधिकारिक समाचार एजेंसी मेहर न्यूज़ के मुताबिक, अल-बुर्श ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो संदेश में चेतावनी दी कि ईंधन की आपूर्ति रुकने से गाज़ा की पहले से ही गंभीर स्वास्थ्य व्यवस्था पर और दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उपलब्ध सीमित ईंधन भी स्वास्थ्य केंद्रों को संचालित रखने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है।

अल-बुर्श ने कहा कि डीज़ल सप्लाई बंद होने का असर केवल अस्पतालों के जनरेटर तक सीमित नहीं रहेगा। उनके मुताबिक, इससे ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इनक्यूबेटर में भर्ती नवजात शिशुओं, डायलिसिस मरीजों, घायलों और गंभीर रूप से बीमार लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। उनके अनुसार एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन और दवाओं तथा वैक्सीन के लिए जरूरी कोल्ड-चेन सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने डब्ल्यूएचओ, दानदाताओं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस फैसले को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। अल-बुर्श ने ईंधन संकट को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक ईंधन उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को ऐसी जानलेवा परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें रोका जा सकता है। हालांकि, डब्ल्यूएचओ की ओर से इस दावे या 19 सितंबर से डीज़ल सप्लाई बंद करने के फैसले पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने विदेश मंत्री शिशिर खनाल से की विदाई मुलाकात

काठमांडू। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बुधवार को नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से विदाई मुलाकात की। सिंहदरबार स्थित विदेश मंत्रालय में हुई मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री खनाल ने राजदूत श्रीवास्तव को सफल कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। विदेश मंत्री खनाल ने नेपाल-भारत संबंधों को और गहरा एवं बहुआयामी बनाने में राजदूत श्रीवास्तव की भूमिका की सराहना की। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग, व्यापार, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति तथा दोनों देशों की जनता के बीच संबंधों पर भी चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान खनाल ने भोटेकोसी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत की ओर से नेपाल के प्रति दिखाई गई एकजुटता तथा आपदा के बाद खोज, बचाव और राहत कार्यों में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त किया।

विदेश मंत्री ने राजदूत श्रीवास्तव के आगामी कार्यकाल और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास जताया कि श्रीवास्तव आगे भी नेपाल के एक अच्छे मित्र के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल के दौरान नेपाल सरकार की ओर से मिले सहयोग और समन्वय के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में नेपाल-भारत संबंध और अधिक मजबूत एवं समृद्ध होंगे।

नेपाल में बाढ़ की वैज्ञानिक वजह तलाशने के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल सरकार ने रसुवा की भोटेकोसी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के वैज्ञानिक आधार और प्रमाण जुटाने के लिए सात सदस्यीय विशेषज्ञ अध्ययन समिति गठित की है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय ने बुधवार को जल नीति विशेषज्ञ देवेश बेल्बासे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। समिति में जल विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्रमान शाक्य, ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ. रिज़नभक्त कायस्थ, रिमोट सेंसिंग विशेषज्ञ डॉ. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डॉ. मेघराज धिताल, जलविद्युत बुनियादी ढांचा विशेषज्ञ डॉ. हरि पंडित और आपदा जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य हैं।

मंत्रालय के प्रवक्ता मोहन शाक्य के अनुसार यह समिति बाढ़ के संभावित उद्गम स्थल से लेकर पूरे तटीय क्षेत्र तक स्थलीय अध्ययन करेगी। अध्ययन का उद्देश्य भोटेकोसी बाढ़ की उत्पत्ति, उससे जुड़े हिमालयी भू-जोखिम, घटनाक्रम और इसमें जलवायु परिवर्तन की संभावित भूमिका का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। जल तथा ऊर्जा आयोग के सचिवालय ने भोटेकोसी बाढ़ को उच्च हिमालयी क्षेत्र में उत्पन्न विभिन्न भूगर्भीय, हिमनदीय और जलवैज्ञानिक जोखिमों के एक-दूसरे से जुड़कर विकसित होने वाली संभावित 'श्रृंखलाबद्ध आपदा' के रूप में अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया था। इसी आधार पर मंत्रालय ने वैज्ञानिक अध्ययन का फैसला लिया है। इससे पहले जल तथा ऊर्जा आयोग के सचिवालय के तहत जलविज्ञान एवं जलस्रोत अनुसंधान केंद्र ने प्रारंभिक अध्ययन किया था। इसमें यह पता

लगाने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले थे कि रसुवा में आपदा की शुरुआत वास्तव में कहां से हुई, किस भौतिक प्रक्रिया से हुई और यह प्रक्रिया ल्हेन्दे-भोटेकोसी नदी प्रणाली के जरिए निचले क्षेत्रों तक कैसे पहुंची। केंद्र ने सुझाव दिया था कि जलवायु परिवर्तन को बाढ़ का कारण घोषित करने से पहले पूरे घटनाक्रम का वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है। अब भूगर्भ, तापमान और पानी से संबंधित सभी पहलुओं का समग्र अध्ययन किया जाएगा। प्रवक्ता शाक्य ने कहा कि भोटेकोसी बाढ़ से त्रिशूली कॉरिडोर प्रभावित हुआ है। भविष्य में इसी तरह की आपदा अन्य नदी प्रणालियों में आने पर ऊर्जा मंत्रालय के विभिन्न बुनियादी ढांचों पर भी सीधा असर पड़ सकता है। इसी वजह से मंत्रालय ने यह अध्ययन शुरू किया है। पहले चरण में उच्च हिमालयी क्षेत्र से लेकर ल्हेन्दे-भोटेकोसी नदी प्रणाली और तटीय क्षेत्र तक घटना के समयक्रम तथा भौगोलिक क्षति का अध्ययन किया जाएगा। इसमें ग्लेशियर, चट्टानों और मिट्टी की ढलानों की अस्थिरता, भूस्खलन, मलबा, नदी के बहाव और बाढ़ के बीच के संबंधों का अध्ययन होगा। दूसरे चरण में बाढ़ के तत्काल और अंतर्निहित भौतिक कारणों की पहचान की जाएगी। तीसरे चरण में मानवजनित जलवायु परिवर्तन ने इन जोखिमों की संभावना, तीव्रता या पहले से मौजूद संवेदनशील परिस्थितियों को कितना प्रभावित किया, इसका वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा।

अमेरिका में बस हादसे की कवरेज के दौरान हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, तीन की मौत

लॉस एंजिल्स,एजेंसी। अमेरिका के लॉस एंजिल्स में मंगलवार शाम एनबीसी4 न्यूज का हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलिकॉप्टर उस समय इलाके में हुई एक बस दुर्घटना की कवरेज कर रहा था। हादसे में फोटो जर्नलिस्ट एलियाना मोरेनो और पायलट जॉर्ज मार्सिनिव समेत तीन लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना लॉस एंजिल्स के सैन फर्नांडो वैली स्थित चैट्सवर्थ इलाके में एक सेल्फ-स्टोरेज सुविधा के पास हुई। लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट (एलएएफडी) के अनुसार, हादसे की सूचना मंगलवार शाम करीब 7 बजे से कुछ समय पहले मिली। हेलिकॉप्टर उस समय इलाके में मौजूद था जब नॉर्डहॉफ स्ट्रीट पर एक लॉस एंजिल्स मेट्रो बस और एक यात्री वाहन के बीच भीषण टक्कर हुई थी।

फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, बस हादसा शाम करीब 5:03 बजे हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। बस हादसे की कवरेज के लिए कई न्यूज़ हेलिकॉप्टर और पत्रकार घटनास्थल पर मौजूद थे। इसी दौरान एनबीसी से जुड़े हेलिकॉप्टर से संपर्क टूट गया। एनबीसी की एंकर कोलीन विलियम्स ने ऑन-एयर इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि स्टेशन को अपने न्यूज़ हेलिकॉप्टर में मौजूद लोगों से संपर्क खोने की जानकारी मिली थी। कुछ देर बाद स्टेशन को हेलिकॉप्टर के चैट्सवर्थ में दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि हुई। एनबीसी लॉस एंजिल्स ने हेलिकॉप्टर में सवार दो

लोगों की पहचान एलियाना मोरेनो और जॉर्ज मार्सिनिव के रूप में की है। मोरेनो 'एंजेल सिटी एयर' की कर्मचारी थीं और एनबीसी तथा उसके स्पेनिश-भाषा वाले सिस्टर स्टेशन टेलीमुंडो 52 के लिए एरियल फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करती थीं। पायलट जॉर्ज मार्सिनिव भी दक्षिणी कैलिफोर्निया से थे और उन्होंने बरबैंक हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। एनबीसी4 और टेलीमुंडो 52 ने संयुक्त बयान जारी कर दोनों की मौत पर गहरा जताया और मृतकों के परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एलएएफडी अधिकारियों ने बताया कि हेलिकॉप्टर क्रैश में कुल तीन लोगों की मौत हुई। इसमें से एक की मौत विमान की चपेट में आने से हुई है।

फायर बटालियन चीफ रिको ए. ग्रॉस ने बताया कि दो अन्य लोगों को अस्पताल ले जाया गया। उनकी स्थिति के बारे में तत्काल विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं थी। क्रैश के बाद हेलिकॉप्टर में आग लग गई, जो पास में खड़ी गाड़ियों तक फैल गई। आग बुझाने के लिए दमकलकर्मियों ने कार्रवाई की। घटनास्थल पर कई वाहन और स्टोरेज कंटेनर भी क्षतिग्रस्त हुए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह अपनी पत्नी एल्योना के साथ गाड़ी से जा रहे थे, तभी उन्होंने हेलिकॉप्टर को असामान्य रूप से कम ऊंचाई पर उड़ते देखा। उन्होंने बताया कि हेलिकॉप्टर धीरे-धीरे ऊंचाई खो रहा था। कुछ ही देर बाद उन्होंने उसे आग की लपटों में घिरते हुए देखा और घटनास्थल के पास रुक गए। बताया कि उन्होंने मलबे के पास एक व्यक्ति को गिरा हुआ देखा, जबकि कुछ अन्य लोग घबराकर चिल्ला रहे थे। हेलिकॉप्टर दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

प्रधानमंत्री शाह से मुलाकात में अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत ने दिया हर मुसीबत में साथ देने का भरोसा

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और नेपाल में अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मेगन बोल्डिन के बीच बुधवार को मुलाकात हुई। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई शिष्टाचार मुलाकात में प्रधानमंत्री शाह ने आपदा की इस कठिन परिस्थिति में नेपाल के प्रति अमेरिकी सरकार की एकजुटता और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस आपदा से नेपाली नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिक भी प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़ी घटना बताया। शाह ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदा के जोखिम को कम करने और उसके प्रभावों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और सामूहिक प्रयासों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में नेपाल की विशिष्ट पर्यटन संभावनाओं और पर्यटन क्षेत्र के विकास के माध्यम से दोनों देशों के लिए पारस्परिक लाभ हासिल करने के अवसरों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि नेपाल अमेरिकी निवेश का हमेशा स्वागत करेगा। कार्यवाहक राजदूत मेगन बोल्डिन ने रसुवा में आई बाढ़ से हुई जन-धन की क्षति पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों और प्रभावित समुदायों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में अमेरिकी सरकार नेपाल सरकार और नेपाली जनता के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। उन्होंने राहत, पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आवश्यक सहयोग और समन्वय करने के लिए अमेरिकी सरकार की तत्परता की भी जानकारी दी।

एक नजर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर बंगाल में शुरू होगी विश्वकर्मा योजना, शुभेंदु अधिकारी ने की घोषणा

कोलकाता,एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से राज्य में विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। कोलकाता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आयोजित पत्रकार वार्ता में शुभेंदु ने कहा कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य में इस योजना को लागू नहीं होने दिया था, लेकिन अब मोदी के जन्मदिन पर इसे शुरू किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर राज्य में भाजपा की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गंगा में एक लाख दीप जलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन को ध्यान में रखते हुए राज्य में भी सेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने यह योजना 19 सितंबर 2023 को शुरू की थी। इसके तहत पात्र कारीगरों और शिल्पकारों को कम ब्याज दर पर तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। राज्य सरकार के अनुसार, इच्छुक लाभार्थी पीएम विश्वकर्मा के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 17 सितंबर को राज्य की 1.58 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में अन्नपूर्णा योजना के तहत तीन योजना रुपये की राशि भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले महीने 1.48 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला था और इस बार करीब 10 लाख अतिरिक्त महिलाओं को योजना के दायरे में लाया गया है। शुभेंदु अधिकारी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पत्रकारों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन का उल्लेख करते हुए उनके कार्यकाल की विभिन्न उपलब्धियां गिनाईं।

नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर सूरत में 1,500 विद्यार्थियों को 10 करोड़ की शिक्षा सहायता, 500 महिलाओं को भी मदद

सूरत,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सूरत में नमो जन सेवा कल्याण समिति द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए विभिन्न जनसेवा गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 1,500 विद्यार्थियों को कुल 10 करोड़ रुपये की शिक्षा सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 500 गंगास्वरूप महिलाओं को भी 50 हजार रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रीनलैब डायमंड के मालिक मुकेश पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जनकल्याण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में परेशानी न हो, इसके लिए सहायता दी जाएगी। समाजसेवी दिनेश नावडिया ने बताया कि ऐसे विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके परिवार में आय का नियमित स्रोत नहीं है, जिनकी माता विधवा हैं या जो मेधावी हैं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई जारी रखने में परेशानी का सामना कर रहे हैं।

अभियान के तहत 500 गंगास्वरूप महिलाओं को प्रत्येक को 50 हजार रुपये तक की सहायता देने की घोषणा की गई है। इसमें एक वर्ष की चिकित्सा सेवा के लिए 12 हजार रुपये, अन्य सहायता के लिए 14,400 रुपये तथा 20 हजार रुपये की अनाज सहायता किट शामिल है। सेवा अभियान के तहत स्वामी विवेकानंद आरोग्य मंदिर के सहयोग से 200 जरूरतमंद लोगों की आंखों की सर्जरी

निःशुल्क की जाएगी। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और कैंसर जांच शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के तीसरे और चौथे चरण के कैंसर मरीजों की देखभाल के लिए भी व्यवस्था की गई है। ऐसे मरीजों को नमो संवेदना केयर सेंटर में दवा, भोजन और रहने की सुविधा सहित सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्र में कुल 25 बिस्तरों की सुविधा है। इसके अलावा बुजुर्ग नागरिकों के लिए दैनिक भोजन के डिब्बे की सेवा तथा जरूरतमंद परिवारों को राशन सहायता भी दी जाएगी। मोटा वराछा स्थित आशादीप प्रशामक देखभाल केंद्र के माध्यम से कैंसर मरीजों के लिए चलाए जा रहे सेवा कार्यों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। मुख्य कार्यक्रम 17 सितंबर को शाम 5 से 7 बजे तक मोटा वराछा के रामचौक स्थित किरण अस्पताल-2 के मैदान में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आयोजकों के अनुसार डायमंड अस्पताल द्वारा बाह्य रोगी विभाग तथा प्रसूति सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम में कथाकार रमेशभाई ओझा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया, वल्लभ लखाणी और पूर्व गृह मंत्री गोरधन झड़फिया सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। इस सेवा अभियान को ग्रीनलैब डायमंड, आशादीप स्कूल, जे. एकलेरा, राजहंस समूह और एसएचजी समूह का सहयोग प्राप्त है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को जनसेवा से जोड़ते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ी सहायता जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

यूपीएल 2026 की टीमें पूरी, 21 सितंबर से होगा तीसरे सीजन का आगाज

देहरादून। उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) के तीसरे संस्करण के लिए सभी सात पुरुष टीमों के स्क्वाड प्लेयर्स ड्राफ्ट के बाद पूरे हो गए हैं। प्रतियोगिता का आयोजन 21 सितंबर से एक अक्टूबर तक रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) के तत्वावधान में होने वाली प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ हरिकेन्स, यूएसएन इंडियंस, नैनीताल टाइगर्स, ऋषिकेश रिवर किंग्स, हरिद्वार एल्मास, टिहरी टाइटन्स और देहरादून वॉरियर्स की टीमें हिस्सा लेंगी। टीमों में सीनियर, अंडर-23, अंडर-19 और अनकैप्ड खिलाड़ियों का संयोजन किया गया है। प्लेयर्स ड्राफ्ट में उत्तराखंड के प्रमुख खिलाड़ियों को विभिन्न टीमों का आइकन प्लेयर बनाया गया है। ऋषिकेश रिवर किंग्स के आइकन प्लेयर आकाश मधवाल, यूएसएन इंडियंस के सुचित जे, नैनीताल टाइगर्स के अवनीश सुधा, हरिद्वार एल्मास के युवराज चौधरी, टिहरी टाइटन्स के तेजस्वी जायसवाल, देहरादून वॉरियर्स के कुणाल चंदेला और पिथौरागढ़ हरिकेन्स के मयंक मिश्रा होंगे।

सीएयू की सचिव किरण वर्मा ने कहा कि प्लेयर्स ड्राफ्ट के जरिए उत्तराखंड की प्रतिभाओं को मजबूत मंच मिला है। उन्होंने कहा कि सीनियर और उभरते खिलाड़ियों के एक साथ आने से तीसरे सीजन में प्रतिस्पर्धा और रोमांच बढ़ेगा। सीएयू के पूर्व सचिव एवं बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष महिम वर्मा ने कहा कि यूपीएल खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल में प्रदर्शन और अपनी क्षमताएं दिखाने का अवसर देता है। उनके अनुसार आईपीएल ऑक्शन चक्र के करीब होने के कारण खिलाड़ियों के लिए यह प्रदर्शन का महत्वपूर्ण मंच हो सकता है। यूपीएल के चेयरपर्सन सुनील जोशी ने कहा कि ड्राफ्ट के बाद लीग में रोमांच बढ़ा है। अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संयोजन उत्तराखंड क्रिकेट में उपलब्ध प्रतिभाओं की गहराई को दर्शाता है। महिला प्रतियोगिता में भी चार टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें मसूरी क्वींस, बागेश्वर एरियल, पिथौरागढ़ हरिकेन्स और देहरादून वॉरियर्स शामिल हैं।

ममता के बांग्लादेश संबंधी बयान को लेकर दायर जनहित याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

कोलकाता,एजेंसी। धर्मतला की सभा से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बांग्लादेश संबंधी टिप्पणी को लेकर दायर जनहित याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने शुरूआत में ही मामले की स्वीकार्यता पर सवाल उठाये थे। बुधवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुग की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उक्त जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले गत एक सितंबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान ममता की टिप्पणी के संदर्भ में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि ममता की टिप्पणी से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है, जिस पर अदालत में मामला चल सके। राज्य की रिपोर्ट के बाद ही मुख्य न्यायाधीश घुग की खंडपीठ ने उक्त जनहित याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि गत दो जून को धर्मतला की सभा से ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को लेकर एक टिप्पणी की थी। तृणमूल नेत्री ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया था। हालांकि, उनका संकेत बांग्लादेश के युवा नेता उस्मान हादी की हत्या की ओर था। इसी को लेकर हाल ही में अभ्रतनु सरकार नामक एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले की एक सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाए थे। हाई कोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती ने सवाल किया था, 'जो कोई भी कुछ कहेगा, क्या अदालत को वह सब सुनना होगा? इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार क्यों किया जाएगा?' नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा था, 'आजकल जनहित याचिका का इस्तेमाल एक विशेष 'टूल' या हथियार के रूप में किया जा रहा है।' ममता से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दिवंगत अभिनेता तथा तृणमूल सांसद तापस पाल के खिलाफ पुराने मामले का भी उल्लेख किया था। दो जून को धर्मतला के वाई चैनल में धरने के दौरान ममता ने कहा था कि बांग्लादेश के एक बड़े हत्यारे को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। जान लीजिए, जिसे लेकर बांग्लादेश में काफी रेवोल्यूशन हुआ था। मैं दूसरे देश की बात नहीं कर रही हूं। मुझे यह कहने का अधिकार नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा, 'लेकिन मैं जो बात कह रही हूं, उसका मुद्दा यह है कि उसके बाद वे मेघालय के रास्ते बंगाल आ गए। जब बंगाल आ गए, तब हमारी एसटीएफ ने उसे पकड़ लिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर प्रत्येक बूथ पर जलेंगे आशीर्वाद के 200 दीये

वाराणसी,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन एवं सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर देश भर में 17 सितम्बर गुरूवार को प्रत्येक बूथ पर 200 'आशीर्वाद का दीया' जलाने का अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सर्किट हाउस में भाजपा और प्रशासन की समन्वय बैठक में दी। उन्होंने बताया कि यह सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 17 सितंबर को सायंकाल पूरे प्रदेश में एक साथ प्रत्येक बूथ पर 200 दीप जलाने का कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दीप जलाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सालों की जनसेवा और संकल्प के प्रति, जनता द्वारा आभार और आशीर्वाद देने का अभियान है। कहा कि आशीर्वाद का दिया जलाने का कार्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी एवं काशीवासी स्वयं करेंगे।

बैठक में सासंद व कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कर्मभूमि काशी से जन्मभूमि वडनगर तक की 22 दिवसीय भव्य बाइक यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर काशी में किया जाएगा। सांसद ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सेवा कार्यों से जोड़ना है। जैसे स्वच्छता, वृक्षारोपण, लाभार्थियों से संवाद, जनचौपाल करना प्रमुख है। उन्होंने बताया कि काशी की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को गुजरात के वडनगर से जोड़ना तथा देश की विविध नदियों, तीर्थ परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है। प्रदेश के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने कहा कि बाइक यात्रा के शुभारंभ से पूर्व काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। इसके पश्चात विधिवत पूजा-अर्चना के साथ वाराणसी से वडनगर तक की 22 दिवसीय बाइक यात्रा प्रारंभ होगी। इस विशेष यात्रा के निमित्त प्रमुख नदियों एवं पवित्र संगमों- गंगा, यमुना, आमी, राप्ती, नर्मदा, गोमती, बेतुआ, अलकनंदा, कुआनो, वरुणा एवं सरयू सहित संगम-का पवित्र जल एकत्रित किया गया है। पार्टी के काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित होने वाले सेवा संकल्प अभियान में शामिल होनें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित अनेक विशिष्ट जन उपस्थित रहेंगे।

युवा शक्ति विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की आधारशिला : पुष्कर सिंह धामी

देहरादून,एजेंसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित 'युवा संकल्प दिवस' कार्यक्रम में कहा कि युवा शक्ति विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण की प्रमुख आधारशिला है। उन्होंने युवाओं से जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करने, नशे से दूर रहने और अपनी सफलता व सामर्थ्य का कुछ हिस्सा प्रदेश के विकास में लगाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिवस को 'युवा संकल्प दिवस' के रूप में मनाए जाने पर प्रदेश के युवाओं का आभार जताते हुए कहा कि जन्मदिवस पर युवा शक्ति के बीच उपस्थित होना उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और संकल्प उन्हें निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की आंखों में उन्हें भविष्य का विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड दिखाई देता है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वर्ष 2047 में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर आज की युवा पीढ़ी विभिन्न क्षेत्रों में देश और प्रदेश के विकास का नेतृत्व कर रही होगी। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने में युवाओं की प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

उन्होंने कहा कि युवाओं को सही दिशा, बेहतर अवसर और पारदर्शी वातावरण उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को रोजगार की तलाश में अपना घर, गांव और प्रदेश छोड़ने की मजबूरी न हो। युवा रोजगार तलाशने वाले ही नहीं, बल्कि उद्यमिता के माध्यम से रोजगार देने वाले भी बनें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और डिजिटल तकनीक रोजगार एवं उद्योग के स्वरूप में तेजी से बदलाव ला रहे हैं। युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक कौशल से जोड़ने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। पर्यटन, होमस्टे और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से भी स्वरोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया है। धामी ने कहा कि राज्य युवा आयोग का गठन युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को नीति निर्माण से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं से संबंधित नीतियों में उनकी आवाज और भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के साथ युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने तथा नशे, साइबर अपराध और अन्य सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक करने में भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवा खेलों में भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद उत्तराखंड की खेलों के क्षेत्र में पहचान और मजबूत हुई है। सरकार खेल सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है।

मिशन 2027 : यूपी में 'लोकमत परिष्कार' के लिए संघ ने कसी कमर, आपसी मतभेद भुलाकर ब्लॉक स्तर तक उतरेंगे कार्यकर्ता

लखनऊ,एजेंसी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को धार देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने समन्वय बैठकें शुरू कर दी है। बुधवार को राजधानी लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिसॉर्ट में भाजपा एवं संघ की समन्वय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष और प्रदेश भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शीर्ष नेताओं ने साफ संदेश दिया कि आगामी चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की एक वैचारिक लड़ाई है। बैठक में आगाह किया गया कि विपक्ष लगातार समाज को बांटने और जातियों में बिखराव पैदा करने का काम कर रहा है। इसके लिए संघ ने 'लोकमत परिष्कार' का संकल्प लिया है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर बेहद संयम, धैर्य और विषय की स्पष्टता के साथ काम करने की नसीहत दी।

ब्लाक स्तर तक के कार्यकर्ताओं से होगा संवाद

संघ से जुड़े विभिन्न आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी अब सीधे ब्लॉक स्तर तक जाकर आम कार्यकर्ताओं और जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। अब जोर आपसी समन्वय को मजबूत करने, आंतरिक मतभेदों को खत्म करने और सीधे ब्लॉक व बूथ स्तर पर जनता के बीच जाकर 'लोकमत परिष्कार' करने पर है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आपसी मतभेदों को पूरी तरह भुलाकर एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरना और विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त करना रहा। बैठक में तय हुआ कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए कार्यकर्ता समाज के बीच संत रविदास, भगवान बिरसा मुंडा और वंदेमातरम के गौरवशाली इतिहास व विषयों को लेकर जाएंगे। भाजपा के 'सेवा संकल्प अभियान' के तुरंत बाद, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर संत रविदास जयंती मनाई जाएगी, जिसके जरिए दलित और वंचित समाज के बीच पैठ मजबूत की जाएगी।

बैठक में अवध और कानपुर के प्रान्तीय पदाधिकारी रहे उपस्थित

समन्वय बैठक के दौरान संगठनात्मक रूप से अति महत्वपूर्ण अवध और कानपुर प्रांत की विशेष बैठक हुई। इसमें दोनों प्रांतों के जमीनी फीडबैक पर चर्चा की गई।संघ की ओर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल, अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक कौशल, सह प्रांत प्रचारक संजय, कानपुर के प्रांत प्रचारक श्रीराम सहित दोनों प्रांतों की प्रांत टोली के चयनित पदाधिकारी और सभी विभाग प्रचारक मौजूद रहे। भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह, अवध क्षेत्र के भाजपा प्रभारी दिलीप पटेल व कानपुर के प्रभारी तथा प्रदेश महामंत्री शंकर लाल लोधी सहित विभिन्न संगठनों के प्रांतीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

उच्च न्यायालय : शिक्षक नियुक्ति विवाद में जेएसएससी की ओर से बहस पूरी, सरकार 30 को रखेगी पक्ष

रांची। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 नियुक्ति से जुड़े मीना कुमारी के मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी की अपील (एलपीए) पर झारखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई। मामले में जेएसएससी की ओर से बहस पूरी हो गई। मामले में महाधिवक्ता रोहित राय ने सरकार की ओर से बहस के लिए समय की मांग की। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए 30 सितंबर का समय दिया। उच्च न्यायालय ने इससे संबंधित अवमानना याचिका के सुनवाई पर रोक जारी रखी है।

उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि मामले में राज्य सरकार एवं जेएसएससी यदि कुछ शपथ पत्र दाखिल करना चाहती है तो 24 सितंबर तक वह दाखिल कर सकती है कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की है। प्रतिवादियों (अभ्यार्थियों) की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता सहित अन्य ने पक्ष रखा। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा। वहीं

सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित सिन्हा ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादियों की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि उक्त नियुक्ति परीक्षा में सरकार की ओर से 17786 पदों के विरुद्ध मात्र 12046 भरे गए हैं। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने प्रार्थियों के प्रतिवेदन के आधार पर योग्य एवं अर्हता पूरी करने वाले 2034 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। उल्लेखनीय है कि डोरंडा स्थित पुराने उच्च न्यायालय बिल्डिंग में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े (स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016) मामले की सुनवाई चल रही है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)